घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 279- रविवार 09- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

अतीक की कब्र के बगल में बेटा दफन....तीनों भाइयों ने कंधा दिया

भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस ने बंदूक की बट मारी,मां शाइस्ता नहीं आई

प्रयागराज,08 अगस्त 2026। अतीक अहमद के 21 साल के बेटे अबान को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है। शनिवार शाम 7 बजे उसे पिता अतीक की कब्र के बगल में दफनाया गया। तीनों भाइयों अली, उमर और अहजम ने अबान को कंधा दिया। जनाजे में शामिल होने के लिए 5-6 हजार लोग पहुंचे। सुरक्षा के लिए कब्रिस्तान के आसपास 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। अबान का शव लेकर उसका भाई अहजम रोते हुए कब्रिस्तान पहुंचा। भीड़ भी उसके पीछे अंदर घुसने लगी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने 2-3 लोगों को बंदूक की बट मारी। इसके बाद भी कुछ युवक अंदर जाने पर अड़े रहे,

तो पुलिसवालों ने थप्पड़ मारकर उन्हें हटाया। भीड़ तितर-बितर हुई तो पुलिसवालों ने खदेड़ दिया। मां शाइस्ता परवीन बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हुई। वह पति अतीक और बेटे असद के जनाजे में भी नहीं पहुंची थी। शाइस्ता 2023 से फरार है। अबान की गुरुवार को सड़क हादसे में मौत हुई थी। अबान को जिस कसारी-मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया। यहीं उसके दादा फिरोज अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद की भी कब्रें हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद अली झांसी जेल और उमर लखनऊ जेल से प्रयागराज पहुंचे। दोनों को आखिरी वक्त में पुलिस वैन से बाहर निकाला गया। बाहर आते ही दोनों भाई एक-दूसरे से गले मिले। इसके बाद मस्जिद में नमाज पढ़ी और अबान को मिट्टी दी। पुलिस ने सिर्फ परिवार और रिश्तेदारों को कब्रिस्तान में जाने की अनुमति दी। अब अली और उमर परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने पैरोल देते समय दोनों को सिर्फ भाई अहजम और बुआ से मिलने की अनुमति दी थी। पुलिस ने कब्रिस्तान से कुछ दूर मस्जिद के बाहर मुलाकात का इंतजाम कराया है। मस्जिद के बाहर टेंट लगाया गया है। इसी में अली-उमर परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। एक घंटे की मुलाकात के बाद पुलिस अली को झांसी और उमर को लखनऊ जेल लेकर रवाना हो जाएगी। अली-उमर को 4 साल में पहली बार पैरोल मिली है।

अखिलेश यादव का तंज,बोले...बेसुध को सब माफ,जनता इन्हें क्षमा करने के मूड में नहीं

लखनऊ,08 अगस्त 2026। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। लखनऊ अग्निकांड में अपना बच्चा खोने वाली एक मां से कथित दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा...'ऐसे लोगों से सभ्य भाषा और अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना ही बेकार है।' अखिलेश ने कहा...कि जनता ऐसे लोगों को माफ करने के मूड में नहीं है और अंत में लिखा- 'अलविदा!'अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा,'बेसुध को सब माफ़!' उन्होंने लिखा,'जो लखनऊ अग्निकांड में उस एक दुखी मां के साथ,जिसने अपना बच्चा खोया हो,कैमरे के सामने सरेआम बदजुबानी और दुर्व्यवहार कर सकते हैं,ऐसे लोगों से सद्-वचन एवं सद्-व्यवहार की अपेक्षा ही निरर्थक है। 'सपा प्रमुख ने आगे कहा...'व्यक्ति को स्वयं का नहीं तो उन पदों का सम्मान करना चाहिए जिस पर वह बैठे हैं या फिर शीघ्र ही वापस जाकर जिस पद पर उन्हें बैठना है। उन्होंने कहा...'वाणी में सरस्वती मां का वास होता है,ये न परलोक की मां का सम्मान करना जानते हैं, न इहलोक की मां का। इनके तो दोनों लोक बिगड़ गए।'अखिलेश यादव ने लिखा,'हमने इन्हें मन से माफ किया क्योंकि वो किसी और के असर में हैं। जाते हुए लोगों से क्या तो शिकवा, क्या शिकायत।' उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में कहा,'जनता इन्हें माफ़ करने के मूड में नहीं है। अलविदा।

न्याय तभी संभव,जब हम पीड़ित के दुःख-दर्द को उसकी भाषा में समझें : न्यायाधीश सूर्यकांत

भोपाल,08 अगस्त 2026। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि दो पक्षों में विवाद के हल में संवाद की प्रक्रिया अनेक विचारों से एकमत या आवाज तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबके न्याय की पहुंच सिर्फ कानून के आधार पर तैयार नहीं हो सकती है। यह संवाद से ही संभव है। उन्होंने कहा कि किसी पीड़ित की समस्या और उसके दुख-दर्द को हमें उसकी अपनी भाषा में अंतर्मन से सुनना पड़ेगा। इससे समस्या को समझने और उसका निदान करने में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा और यही अंतिम न्याय का आधार बनेगा। न्यायाधीश सूर्यकांत शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस-'इन्हेंसिंग एक्सेस जस्टिस' के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान न्यायाधीश सूर्यकांत, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायमूर्तिगणों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। यह कॉन्फ्रेंस 9 अगस्त तक चलेगी। कॉन्फ्रेंस का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (नालसा),मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर (सालसा) और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स को कई सीख दीं...

मैं बाबा बागेश्वर तो नहीं हूं...लेकिन कुछ तो चलता होगा : पीएम मोदी

नई दिल्ली,08 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को उनकी नई शुरुआत के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से मजाकिया अंदाज में कहा कि आज सभी छात्र दीक्षांत समारोह में मौजूद हैं,लेकिन उनके मन में भविष्य को लेकर कुछ न कुछ जरूर चल रहा होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैं बाबा बागेश्वर तो नहीं हूं,लेकिन कुछ तो चलता होगा।' पीएम मोदी ने कहा कि हर छात्र के मन में आने वाले कल की अलग-अलग तस्वीर होती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि दुनिया और प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है और आने वाले समय में वही व्यक्ति और समाज आगे बढ़ेगा,जो लगातार सीखने के लिए तैयार रहेगा। उन्होंने युवाओं से अपनी जिज्ञासा को जीवित रखने,सवाल पूछने और नई चुनौतियों के नए समाधान खोजने का साहस रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

(आईआईटी) दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया का रणनीतिक समीकरण और वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत प्रौद्योगिकी की गति है। कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी,लेकिन बदलाव के हर दौर में चुनौतियों के साथ नए अवसर भी पैदा होते हैं। उन्होंने कहा,'दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी, इंडस्ट्री बदलेगी और प्रोफेशन भी बदलेंगे, लेकिन इन सबके बीच मेरी बात याद रखिएगा-जो सीखेगा,वो जीतेगा।'उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नई चुनौतियों के नए समाधान खोजने का साहस रखेगा, उसके लिए चुनौतियां ही अवसर बन जाएंगी। यही सोच आईआईटी दिल्ली ने विद्यार्थियों को सिखाई है।

समारोह में 3,000 से अधिक स्नातकों को डिग्रियां प्रदान की गईं,जिनमें 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल,शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट टेन गोल्ड मेडल भी प्रदान किए। उन्होंने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित एआई आधारित हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटिंग सुविधा 'परम प्रज्ञा'का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने दीक्षांत समारोह में शामिल विद्यार्थियों को जीवन के नए अध्याय की शुरुआत के लिए बधाई देते हुए कहा कि आज उनके परिवारों को जिस तरह अपने बच्चों पर गर्व हो रहा है, उसी तरह उन्हें भी सभी विद्यार्थियों पर गर्व है। विद्यार्थी केवल डिग्री लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि देश के लिए कुछ करने के सपने लेकर निकल रहे हैं।

मोदी ने कहा कि हर विद्यार्थी के मन में भविष्य की अलग तस्वीर होगी। कोई पहली नौकरी और पहली तनख्वाह का इंतजार कर रहा होगा,कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी कर रहा होगा,कोई अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहा होगा तो किसी ने अगली प्रतियोगी परीक्षा का लक्ष्य बनाया होगा। उन्होंने कहा कि रास्ते और सपने भले ही अलग हों, लेकिन आईआईटी दिल्ली में प्रवेश से लेकर दीक्षांत तक की यात्रा सभी के लिए यादगार है।

अमरनाथ यात्रा 20 दिन पहले रोकी गई...बारिश और लैंडस्लाइड से रास्ते खराब होने के कारण फैसला

नई दिल्ली,08 अगस्त 2026। बाबा अमरनाथ की यात्रा तय समय से 20 दिन पहले रोक दी गई है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के कारण रास्ते खराब हो जाने के कारण यह फैसला लिया गया। अब जो जत्थे यात्रा पर हैं, उन्हीं की यात्रा पूरी कराई जाएगी। नए जत्थे नहीं भेजे जाएंगे। अब तक 4.8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने बताया कि IMD ने अगले कुछ दिनों में खराब मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त से दोनों रूट पर यात्रा रोकने का फैसला किया गया है।

यात्रा भले ही 9 अगस्त से श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएगी,लेकिन पारंपरिक छड़ी मुबारक कार्यक्रम के साथ इसका धार्मिक समापन होगा। पवित्र छड़ी 28 अगस्त को पारंपरिक पहलगाम मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाएगी और इसी के साथ अमरनाथ यात्रा-2026 का औपचारिक समापन होगा।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जेपीएससी परीक्षा विवाद...याचिका में छात्रों ने की मामले की सीबीआई जांच की मांग

नई दिल्ली,08 अगस्त 2026। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा एक बार फिर बड़े विवादों के घेरे में आ गई है। 14 वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली और अनियमितताओं की गूंज अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की ओर से शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका के सामने आने के बाद से परीक्षा में शामिल हुए हजारों युवाओं की नजरें अब अदालत के फैसले पर टिक गई हैं। राज्य में छात्र संगठन पहले से ही सड़कों पर उतरकर भर्ती प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में यह मामला डायरी नंबर 47998/2026 के तहत दर्ज कर लिया गया है। इस याचिका में 19 अप्रैल को आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल

खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि परीक्षा के प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, ओएमआर शीट की कस्टडी और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के तरीके की समयबद्ध जांच कराई जाए। याचिका में मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपी जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी अन्य हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए। इस पूरे विवाद की मुख्य वजह 2 जुलाई को घोषित हुआ परीक्षा परिणाम है।

रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही इंटरनेट पर एक सफल उम्मीदवार की ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी तेजी से वायरल होने लगी।

रील 21वीं सदी का नशा है...हजार में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी,सिस्टम युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा रहा : राहुल

प्रयागराज,08 अगस्त 2026। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को 20 मिनट तक संबोधित किया। राहुल के साथ प्रियंका गांधी की बेटी मिराया भी रहीं। राहुल ने कहा...आपसे कहा जाता है कि जितनी रील देखनी है और जितनी रील बनाना चाहते हैं,बनाओ। यह रील 21वीं सदी का नशा है। 1 हजार युवाओं में से केवल 12 को ही स्थायी नौकरी मिलती है। युवाओं का डेटा छीनकर बड़ी-बड़ी कंपनियों को दिया जाता है। भारत में करीब 40 करोड़ युवा हैं। यही देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। चीन की चर्चा होती है, लेकिन भारत के युवाओं के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवारों से लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और बदले में बीए-एमए की डिग्री मिलती है,लेकिन यह सर्टिफिकेट रोजगार की गारंटी नहीं देता।

राहुल बोले...स्टूडेंट के दिल में मोहब्बत होनी चाहिए...

राहुल बोले...तो ये थी बिहार और यूपी की आवाज। अब मैंने आपसे कहा कि आपने अंधेरे में टार्च जला दी। आप सब बात समझ गए। स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने पिछली स्लाइड में मोदी,भागवत,

अडाणी की फोटो दिखाई,लेकिन आपको सिस्टम को खत्म टाटा बॉय बॉय करना है। ये सब आपको प्यार के साथ करना है। मैं आपके साथ खड़ा हूं और आगे भी रहूंगा।

छात्र बोला...दो ही ऑप्शन, चाय बेचूं या सुसाइड करूं

राहुल से एक छात्र बोला...मेरे पास दो ऑप्शन हैं,या तो चाय की दुकान खोलूंगा या सुसाइड करूंगा। इस पर राहुल ने कहा... कि सुसाइड कोई समाधान नहीं होता भाई। उन्होंने छात्र से पूछा- क्या आपकी फैमिली ने कर्ज लिया? इस पर छात्र बोला...मैंने जमीन बेचकर बीएड किया। अब नौकरी की तलाश में हूं। मैं सम्राट चौधरी के गुंडे से नहीं डरूंगा।

राहुल से छात्रा ने कहा... पुलिस ने एके-47 चलाई

राहुल ने बिहार की छात्रा से बात की। उसने बताया...बिहार पुलिस ने पटना में प्रदर्शनकारियों को पीटा। 23 जुलाई को हमने एक और प्रोटेस्ट रखा। लेकिन उससे पहले पुलिस और आरएएफ मौजूद था। फिर अगले दिन सिवान में पुलिस ने एके-47 चलाई। एक छात्र की मौत हो गई। 25 जुलाई को आप जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे थे। तब हम बिहार में डरे बैठे थे, कब कहां से पुलिस हमें उठा ले जाए। लाइब्रेरी से छात्रों को ले गई। एक छात्र ने स्टेज पर आकर बताया कि 22 जुलाई को पटना में प्रदर्शन के दौरान हमारे ऊपर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। उनका टारगेट था सिर पर मारो या पैर में। आंसू गैस के गोले छोड़े। इनकी वर्दी में बैच भी नहीं थे। ये एंबुलेंस नहीं आने दे रहे थे। थ्री इडियट मूवी की तरह स्कूटी में अस्पताल ले गया। बाद में मुझे 15 घंटे थाने में बिठाया गया। हम पहले नौकरी के लिए आंदोलन करें, फिर पेपर के लिए करें, फिर रिजल्ट के लिए करें। अरे हम छात्र हैं या आंदोलनजीवी हैं।

राहुल का सरकार से सवाल...महिला आरक्षण लागू क्यों नही किया,इसे परिसीमन से क्यों जोड़ रहे

नई दिल्ली,08 अगस्त 2026। राहुल गांधी ने शनिवार को कहा...कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही संसद से सर्वसम्मति से पास हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन किया था। लेकिन तीन साल बाद भी कानून लागू नहीं किया गया है। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल किया कि महिला आरक्षण कानून को लागू करने में देरी क्यों हो रही है और इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है। उन्होंने सरकार से 2023 में पारित कानून को बिना किसी शर्त के लागू करने की मांग की। महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने का मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है और इसे पूरी तरह लागू करने की बात कहता रहा है। जबकि सरकार परिसीमन के जरिए

लोकसभा सीटें बढ़ाकर इसे लागू करने की बात कह रही है। दरअसल,राहुल ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि भारत की महिलाओं को खुद को एक्सप्रेस करने की, कल्पना करने की मंजूरी नहीं है। कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वहां की महिलाएं खुद को एक्सप्रेस न करें।

महिला आरक्षण पर रिजिजू का राहुल पर पलटवार,कहा... 2029 में लागू करने के लिए जल्द परिसीमन जरूरी

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर शनिवार को पलटवार करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम-2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में किया जा चुका है,लेकिन इसके लागू होने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया आवश्यक है। रिजिजू ने एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि महिला आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद किए जाने वाले परिसीमन के आधार पर प्रभावी होगा। वर्ष 2023 के बाद प्रकाशित होने वाली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाना है और मौजूदा जनगणना प्रक्रिया जारी है।

एनयूसीएफडीसी का मुख्यालय दिल्ली से मुंबई स्थानांतरित : अमित शाह

मुंबई,08 अगस्त 2026। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मुंबई में कहा कि नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनयूसीएफडीसी) का मुख्यालय दिल्ली से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है। अमित शाह ने मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में एनयूसीएफडीसी के नए मुख्यालय का उद्घाटन भी किया। मुंबई के बीएसई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एनयूसीएफडीसी कन्वेंशन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में देश के सबसे अधिक शहरी सहकारी बैंक हैं और यहां देश के सबसे पुराने सहकारी

आंदोलनों में से एक भी रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वर्तमान में 449 सहकारी बैंक हैं। महाराष्ट्र,गुजरात,गोवा और कर्नाटक मिलकर देश के करीब 70 प्रतिशत सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी को देखते हुए एनयूसीएफडीसी का मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। शाह ने इससे पहले एनयूसीएफडीसी के साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का भी शुभारंभ किया।

हिमाचल में यात्रियों से भरी बस पलटी,7 की मौत

50 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर गिरी,अंदर फंसे एक दूसरे पर गिरे लोग

भरमौर,08 अगस्त 2026। हिमाचल प्रदेश के चंबा में शनिवार सुबह एक प्राइवेट बस पलट गई। जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। हादसे में 11 यात्री घायल हो गए। जिन्हें तीसा अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। SP विजय कुमार सकलानी ने बताया कि बस सुबह 7 बजे बैरागढ़ से चंबा के लिए चली थी। बैरागढ़ से कुछ ही दूरी पर 'शर्मा कोच'बस चालुंज मोड़ के पास बेकाबू होकर पलटी, फिर 50 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार-बस पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। अंदर फंसे लोग एक दूसरे पर जा गिरे। जेसीबी की मदद से बस को तोड़ा गया, फिर अंदर फंसे मृतकों और घायलों को बाहर

निकाला गया। इस दौरान लोग बचाव-बचाव चिल्लाते सुने गए।

18 के करीब यात्री सवार थे : पुलिस के अनुसार-बस नंबर एचपी-73-ए-2101 में ड्राइवर-कंडक्टर समेत 18 यात्री सवार थे। इनमें चार से 18 साल के छह बच्चे भी शामिल है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को तीसा अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय प्रशासन ने सभी घायलों को 5-5 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान कर दी है,जबकि मृतकों के परिजनों को भी जल्द राहत राशि दी जाएगी।

गवर्नर-सीएम ने शोक जताया

हिमाचल के गवर्नर कविन्द्र गुप्ता, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू,डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री,नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिक्षा सिंह ने बस हादसे में 7 लोगों के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनां व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। सीएम ने जिला प्रशासन को सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराकर उनके समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएम विजय को बड़ा झटका : परिसीमन बैठक से 37 सांसदों ने बनाई दूरी....

चेन्नई,08 अगस्त 2026। तमिलनाडु में परिसीमन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विजय थलपति की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय सांसदों की बैठक को विपक्षी दलों के बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। शनिवार को चेन्नई में प्रस्तावित इस बैठक से राज्य के 57 में से 37 सांसदों ने दूरी बनाने का फैसला किया है। ऐसे में बैठक में करीब 20 सांसदों के शामिल होने की संभावना है। इसे मुख्यमंत्री विजय की परिसीमन को लेकर साझा राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बैठक के बहिष्कार में मुख्य भूमिका डीएमके की है। पार्टी के सभी 30 सांसदों ने बैठक में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। इसके अलावा एआईएडीएमके के चार सांसदों के साथ PMK, MNM और DMDK के एक-एक सांसद भी बैठक से दूर रहेंगे। विपक्षी दलों के इस रुख से बैठक में व्यापक सर्वदलीय भागीदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के करीब 20 सांसद बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। इनमें कांग्रेस के

12,VCK के दो,CPI के दो,CPI(M) के दो, एमडीएमके का एक और IUML का एक सांसद शामिल है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने बैठक को लेकर मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब केंद्र सरकार की ओर से मौजूदा संसद सत्र में परिसीमन से संबंधित किसी नए विधेयक को पेश करने की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, तो इस तरह की बैठक का कोई औचित्य नहीं है।

संपादकीय

असहमति से असहिष्णुता तक

संविधान सभा स्वतंत्र भारत के संविधान को अंतिम रूप देने के ऐतिहासिक क्षण के निकट थी। तब डा. भीमराव आंबेडकर ने एक ऐसी चेतावनी दी थी,जिसकी प्रतिध्वनि आज भी सुनाई देती है। उन्होंने कहा था कि जब संवैधानिक उपाय उपलब्ध हों,तब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए असंवैधानिक रास्तों का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

लगभग आठ दशक बाद इस चेतावनी को नए संदर्भ में पढ़ने की आवश्यकता है। आज प्रश्न यही नहीं है कि हम असहमति कैसे व्यक्त करें। उससे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम दूसरे की असहमति को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार कर सकते हैं,जितनी दृढ़ता से अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार चाहते हैं? यहीं से आज के लोकतांत्रिक विमर्श की एक गंभीर चिंता उपजती है।

आंदोलन लोकतंत्र के लिए अपरिचित नहीं हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम स्वयं जन-आंदोलनों की महान परंपरा से निकला है। स्वतंत्र भारत में भी आंदोलनों ने शासन को नागरिकों की अपेक्षाओं के प्रति सजग किया है,अनेक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया है और हाशिए की आवाजों को सार्वजनिक विमर्श के केंद्र तक पहुंचाया है। इसलिए आंदोलन को लोकतंत्र की कमजोरी मानना उचित नहीं होगा। शांतिपूर्ण असहमति लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है।

गांधी जी की पूरी राजनीतिक पद्धति में साधन की शुचिता को लक्ष्य की पवित्रता जितना ही महत्व मिला। इसीलिए गांधीवादी असहमति प्रतिद्वंद्वी को नष्ट करने के बजाय उसके अंतःकरण से संवाद करने का प्रयास करती थी। लोकतंत्र का संस्कार भी कुछ ऐसा ही है। मैं आपसे असहमत हूं,इसलिए आपका विरोध कर सकता हूं,लेकिन केवल इसलिए आपकी गरिमा,आपके अधिकार और आपकी लोकतांत्रिक वैधता को अस्वीकार नहीं कर सकता। यह सिद्धांत सत्ता और आंदोलनकारियों, दोनों पर समान रूप से लागू होता है।

सत्ता यदि प्रत्येक असहमति को शत्रुता अथवा अवज्ञा मानने लगे, तो लोकतांत्रिक संवाद कमजोर होता है। उसी प्रकार आंदोलनकारी यदि प्रत्येक असहमत नागरिक को सत्ता का समर्थक या अपने संघर्ष का विरोधी मान लें, तो आंदोलन की लोकतांत्रिक नैतिकता प्रभावित होती है। लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, दूसरे की आवाज सुनने का संस्कार भी उतना ही आवश्यक है। आज सार्वजनिक जीवन में यही संतुलन विशेष महत्व रखता है। इंटरनेट मीडिया ने प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति का अभूतपूर्व मंच दिया है, लेकिन उसने त्वरित प्रतिक्रियाओं, आरोपों और वैचारिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ाया है। कई बार हम तर्क सुनने से पहले व्यक्ति की पहचान देखते हैं और विचार पढ़ने से पहले यह तय कर लेते हैं कि वह किस 'पक्ष' का है। परिणाम यह होता है कि बहस सत्य की खोज से हटकर अपने-अपने खेमे की विजय का माध्यम बनने लगती है। यहीं से लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर संकट पैदा होता है-भरोसे का संकट।

लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि वह हमें एक जैसा बनाने का प्रयास नहीं करता। लोकतंत्र को केवल चुनावों से नहीं मापा जा सकता। चुनाव उसका अनिवार्य आधार हैं, लेकिन लोकतांत्रिक संस्कृति उससे कहीं व्यापक है। वह तीन प्रकार के भरोसे पर खड़ी होती है-नागरिक का नागरिक पर भरोसा,नागरिक का संस्थाओं पर भरोसा और संस्थाओं का नागरिक के विवेक पर भरोसा। इनमें से कोई एक कमजोर होता है तो पूरी लोकतांत्रिक संरचना प्रभावित होती है। आज के विवादों और आंदोलनों को भी इसी कसौटी पर देखने की आवश्यकता है। कौन जीता और कौन हारा,इसका उत्तर अलग-अलग राजनीतिक दृष्टियों से अलग हो सकता है। कोई आंदोलनकारियों के प्रश्नों को अधिक न्यायसंगत बताएगा। लोकतंत्र इन दोनों मतों के लिए स्थान देता है, लेकिन एक तीसरा प्रश्न दोनों से बड़ा है-इस पूरे संघर्ष के बाद लोकतंत्र पर जनता का भरोसा कितना बचा?

यदि विवाद समाप्त होने के बाद नागरिक एक-दूसरे को अधिक संदेह से देखने लगें,संस्थाओं की निष्पक्षता पर विश्वास कमजोर हो जाए,सरकार और विपक्ष के बीच संवाद असंभव-सा लगने लगे तथा सार्वजनिक जीवन 'हम' और 'वे' में विभाजित हो जाए,तो किसी पक्ष की तात्कालिक राजनीतिक जीत भी लोकतंत्र की दीर्घकालिक उपलब्धि नहीं कही जा सकती। राजनीतिक विजय क्षणिक हो सकती है,संस्थागत अविश्वास की उम्र बहुत लंबी होती है। इसीलिए आंबेडकर की संवैधानिक चेतावनी आज और महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में प्रश्न पूछना अधिकार है,किंतु आरोप के साथ प्रमाण का दायित्व भी है। सत्ता को निर्णय लेने का अधिकार है, किंतु उसके साथ पारदर्शिता और जवाबदेही का दायित्व भी जुड़ा है।

संस्थाओं को निष्पक्ष होना चाहिए और उनकी कार्यप्रणाली में निष्पक्षता दिखाई भी देनी चाहिए। लोकतंत्र का उत्तर अधिक लोकतंत्र है-अधिक संवाद, अधिक पारदर्शिता और अधिक भरोसा। लोकतंत्र में असहमति समस्या नहीं है। असहमति को सह न पाना समस्या है और जब असहिष्णुता संवाद को विस्थापित करती है,तो उसका अंतिम शिकार भरोसा होता है। लोकतंत्र में कोई चुनाव हार सकता है,कोई बहस हार सकता है, कोई आंदोलन भी अपने तात्कालिक लक्ष्य में असफल हो सकता है, लेकिन यदि इस प्रक्रिया में भरोसा हार गया,तो अंततः हार लोकतंत्र की होगी।

सुविचार

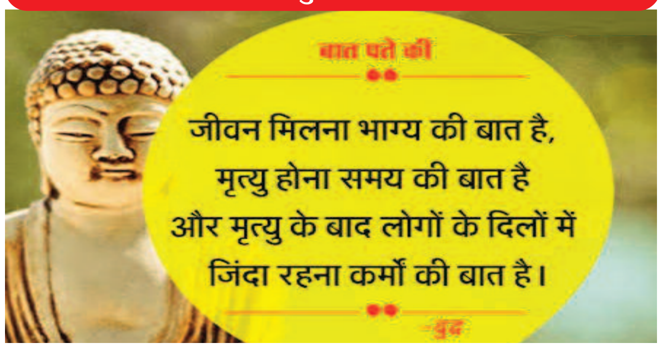

दवाएँ बनीं जीवन की उम्मीद,लेकिन कीमतें बनीं सबसे बड़ी दीवार

एक बीमारी नहीं,पूरा परिवार लड़ता है हर महँगे इलाज से... रोग से रण,खर्च से हार-भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था का कठोर सच...

प्रो. रितेश कुमार जैन
बड़वानी, मध्यप्रदेश

समय ने ऐसी करवट ली है कि अब सबसे बड़ा डर बीमारी नहीं,बल्कि उसके उपचार का भारी बोझ बन चुका है। रोग का असर केवल शरीर तक सीमित रहता है, लेकिन दवाओं और इलाज का खर्च पूरे परिवार की आर्थिक शक्ति को भीतर तक चकनाचूर कर देता है। अस्पतालों की चौखट पर अब सिर्फ स्वास्थ्य की लड़ाई नहीं लड़ी जाती;वहाँ यह भी तय होता है कि किसकी आर्थिक क्षमता जीवन को बचा पाएगी और किसका जीवन पैसों की कमी के सामने हार मान लेगा। यही वह बिंदु है,जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप निर्वस्त्र होकर सामने खड़ा दिखाई देता है।

भारतीय स्वास्थ्य परिदृश्य आज ऐसे दो संकटों का सामना कर रहा है, जिनकी प्रकृति भले अलग हो, पर दोनों एक ही नैतिक चुनौती को उजागर करते हैं। एक तरफ कैंसर है,जो अब न उम्र की सीमाओं में बँधा है, न किसी क्षेत्र या वर्ग तक सीमित। इसकी बढ़ती रफ्तार किसी मौन महामारी जैसी प्रतीत होती है। महानगरों से दूरस्थ गाँवों तक,युवाओं से बुजुर्गों तक,इसकी पकड़ निरंतर गहरी होती जा रही है। दूसरी तरफ दुर्लभ बीमारियाँ हैं,जो सुर्खियाँ नहीं बनतीं, लेकिन असंख्य परिवारों को वर्षों तक आर्थिक,मानसिक और सामाजिक संघर्ष में जकड़े रखती हैं। रोग दोनों अलग हैं,किंतु उनकी सबसे बड़ी त्रासदी एक ही है–जीवनरक्षक दवाएँ आज भी सामान्य नागरिक की पहुँच से बहुत दूर हैं।

सरकारी नीतियों की सबसे बड़ी कसौटी संकट के समय सामने आती है, और यहीं उनका सबसे गहरा विरोधाभास भी उजागर होता है। हमारे निर्णय अक्सर बीमारी की गंभीरता नहीं,बल्कि मरीजों की संख्या देखकर लिए जाते हैं। कैंसर के बढ़ते मामलों ने कुछ जीवनरक्षक दवाओं को निःशुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराने की राह अवश्य खोली है, लेकिन यह व्यवस्था अब भी सीमित है। दूसरी ओर,दुर्लभ बीमारियों में मरीज कम होने के कारण सहायता भी सीमित कर दी जाती है। मानो कम लोगों की पीड़ा का मूल्य भी कम हो,जबकि मृत्यु कभी बहुमत और अल्पमत में भेद नहीं करती।

इलाज की परीक्षा अस्पताल से बाहर शुरू होती है,जब दवाओं का खर्च वर्षों तक परिवार का पीछा नहीं छोड़ता। कैंसर का उपचार ऑपरेशन या कीमोथेरेपी तक सीमित नहीं रहता। बीमारी का पता देर से चलता है,उपचार लंबा खिंचता है और नई पीढ़ी की प्रभावी दवाएँ इतनी महँगी होती हैं कि मध्यम वर्ग कुछ महीनों में आर्थिक रूप से बिखर जाता है। दुर्लभ बीमारियों में संकट कठोर होता है। सरकारी नीति के तहत प्रति मरीज ₹50 लाख तक सहायता मिलती है। शुरुआती राहत मिलती है, लेकिन कई बीमारियों में सालाना खर्च अधिक और दवा की जरूरत लगातार रहती है। उपचार टूटते ही मरीज फिर संकट में खड़ा हो जाता है।

योजनाओं की प्रभावशीलता वहीं समाप्त होती है जहाँ उपचार का खर्च असाधारण हो जाता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ सामान्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में उपयोगी हैं, पर अत्यधिक महँगी व लंबी अवधि की जीवनरक्षक दवाओं का खर्च नहीं उठा पातीं। दुर्लभ बीमारियों की सहायता योजनाएँ (प्रति मरीज ₹50 लाख तक) भी उपचार की पूरी अवधि कवर नहीं कर पातीं। कैंसर में नई प्रभावी दवाएँ निःशुल्क उपलब्धता से बाहर हैं। परिणाम–विज्ञान ने इलाज खोज लिया, व्यवस्था उसे लोगों तक नहीं पहुँचा सकी।

स्वास्थ्य नीति की अगली दिशा राहत नहीं, बल्कि अधिकार पर आधारित हो। अब उपचार की अवधारणा को अनुदान से अधिकार की ओर ले जाना होगा। पहली आवश्यकता है कि कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। सहायता एकमुश्त अनुदान तक सीमित न रहे। बीमारी जितनी अवधि तक उपचार चाहती है,उतनी अवधि तक दवा उपलब्ध कराना व्यवस्था का दायित्व हो। निःशुल्क या अत्यंत रियायती दवा सरकारी कृपा नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार बने।

समाधान की अगली कड़ी दवाओं की खरीद और उत्पादन व्यवस्था में बदलाव से जुड़ी है। इस परिवर्तन का दूसरा आधार केंद्रीय स्तर पर दवाओं की थोक खरीद हो सकता है। सरकार यदि बड़े पैमाने पर खरीद करे,तो कीमतों पर नियंत्रण आसान होगा। इसके साथ ही आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को गति देनी होगी। जितनी शीघ्र इन दवाओं का उत्पादन देश में बढ़ेगा,उतनी ही जल्दी आयात पर निर्भरता घटेगी, कीमतें कम होंगी और आपूर्ति स्थिर होगी।

स्वास्थ्य व्यवस्था तभी प्रभावी मानी जाएगी,जब उपचार दवा से आगे बढ़कर पूरी चिकित्सा प्रक्रिया को समेटे। उपचार का अर्थ केवल दवा उपलब्ध करा देना नहीं है। समय पर निदान और विशेषज्ञ चिकित्सा संस्थान भी उतने ही आवश्यक हैं। इसलिए कैंसर के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। दुर्लभ बीमारियों के लिए अभी 15 उत्कृष्ट केंद्र चल रहे हैं,फिर भी हर बड़े राज्य में पूर्ण सुविधाओं वाले विशेष उपचार केंद्र बनाए जाएँ,ताकि मरीज केवल कुछ महानगरों पर निर्भर न रहें। सफल व्यवस्था के लिए संसाधनों के साथ जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन भी अनिवार्य है। महँगी दवाओं की खरीद, अनुसंधान और राष्ट्रीय नीति का दायित्व केंद्र सरकार उठाए,जबकि वितरण, उपचार की निरंतर निगरानी और अनुवर्ती देखभाल की जिम्मेदारी राज्यों के पास हो। जब उत्तरदायित्व स्पष्ट होंगे,तभी मरीज विभागों और कागजी प्रक्रियाओं में उलझने के बजाय उपचार पर ध्यान दे सकेंगे।

शासन की सबसे बड़ी परीक्षा सबसे कमजोर नागरिक के प्रति जिम्मेदारी है। यह प्रश्न केवल स्वास्थ्य नहीं, संवेदनशीलता का है। बजट सीमित हो सकता है,लेकिन प्राथमिकताएँ राजनीतिक इच्छाशक्ति तय करती हैं। इसलिए स्वास्थ्य बजट का हिस्सा कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए आरक्षित हो। जब रोग सीमाएँ तोड़ देते हैं, शासन भी पुरानी सोच से बँधा नहीं रह सकता। जीवनरक्षक दवा संख्या नहीं,पीड़ा देखकर उपलब्ध कराना ही उस भारत की पहचान बनेगा,जहाँ किसी गरीब की साँस दवा की कीमत से छोटी नहीं होगी।

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

माइंडफुल करियर : उद्देश्य के साथ करियर चुनें,दबाव के साथ नहीं

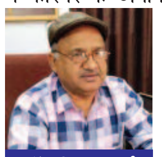
डॉ. विजय गर्ग
मलोट पंजाब

आज का युग अवसरों का युग है। विज्ञान,प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता , डिजिटल क्रांति और वैश्विक अर्थव्यवस्था ने करियर के अनगिनत नए रास्ते खोल दिए हैं। लेकिन विकल्प जितने बढ़े हैं, भ्रम भी उतना ही बढ़ा है। आज का युवा अक्सर इस दुविधा में रहता है कि कौन-सा करियर चुने–वह जो समाज चाहता है, वह जो परिवार चाहता है,या वह जो उसका अपना मन चाहता है। ऐसे समय में माइंडफुल करियर की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

माइंडफुल करियर का अर्थ है ऐसा करियर चुनना जो केवल वेतन या प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं,बल्कि व्यक्ति की रुचि,योग्यता,मूल्यों और जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। यह सोच-समझकर,स्वयं को पहचानकर और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय है।

करियर की शुरुआत स्वयं को समझने से होती है। हर व्यक्ति की क्षमताएँ,रुचियाँ और व्यक्तित्व अलग-अलग होते हैं। कोई गणित में अच्छा होता है, कोई कला में,कोई विज्ञान में,तो कोई लोगों से संवाद स्थापित करने में। यदि कोई छात्र केवल दूसरों की देखा-देखी किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है,तो संभव है कि वह आर्थिक रूप से सफल हो जाए, लेकिन मानसिक संतुष्टि प्राप्त न कर सके। इसलिए करियर चुनने से पहले यह जानना आवश्यक है कि हमें वास्तव में किस प्रकार का कार्य प्रेरित करता है।

दुर्भाग्य से हमारे समाज में आज भी अनेक करियर निर्णय सामाजिक दबाव में लिए जाते हैं। कई छात्र डॉक्टर या इंजीनियर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि परिवार की अपेक्षा होती है। कुछ सरकारी नौकरी को ही सफलता का पर्याय मानते हैं। वहीं कुछ युवा अपने मित्रों की नकल करते हुए उसी क्षेत्र में चले जाते हैं। परिणामस्वरूप अनेक लोग वर्षों तक ऐसे काम में लगे रहते हैं जिसमें उनका मन नहीं लगता। माइंडफुल करियर हमें यह सिखाता है कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय तुलना के आधार पर नहीं,बल्कि आत्मबोध के आधार पर लिए जाने चाहिए। आज का रोजगार जगत तेजी से बदल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और डिजिटल तकनीक ने अनेक पारंपरिक नौकरियों का स्वरूप बदल दिया है। वहीं डेटा साइंस,साइबर सुरक्षा,नवीकरणीय ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी,डिजिटल मार्केटिंग,गेम डेवलपमेंट,कंटेंट क्रिएशन,पर्यावरण प्रबंधन और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए माइंडफुल करियर का अर्थ केवल वर्तमान को देखना नहीं,बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी समझना है।

एक सफल करियर केवल डिग्री पर निर्भर नहीं करता,बल्कि सीखते रहने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। आज जीवन भर सीखना एक आवश्यकता बन चुका है। नई तकनीकों को अपनाना, नए कौशल विकसित करना और समय के साथ स्वयं को अपडेट रखना ही भविष्य की सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धा से पीछे छूट जाता है।

करियर का उद्देश्य केवल अधिक आय अर्जित करना नहीं होना चाहिए। यदि किसी कार्य में अर्थ, संतोष और समाज के प्रति योगदान का भाव हो,तो वह व्यक्ति को अधिक प्रेरित करता है। एक अच्छा शिक्षक,ईमानदार डॉक्टर, संवेदनशील पत्रकार,कुशल वैज्ञानिक,समर्पित किसान या नवाचारी उद्यमी–सभी समाज के विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए किसी भी पेशे का सम्मान उसके वेतन से नहीं,बल्कि उसके योगदान से होना चाहिए।

माता-पिता और शिक्षकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों पर अपनी अधूरी इच्छाएँ थोपने के बजाय उनकी रुचियों और क्षमताओं को समझना अधिक आवश्यक है। यदि परिवार सहयोगी वातावरण प्रदान करे, विभिन्न करियर विकल्पों की जानकारी दे और बच्चों को स्वतंत्र सोचने का अवसर दे,तो वे अधिक संतुलित और सफल निर्णय ले सकते हैं। करियर काउंसलिंग,इंटर्नशिप,प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा और उद्योगों से जुड़ाव भी इस दिशा में उपयोगी कदम हैं।

मानसिक स्वास्थ्य भी करियर से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति अपनी रुचि के विपरीत कार्य करता है,तो तनाव, निराशा और बर्नआउट की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत, यदि व्यक्ति अपने पसंदीदा क्षेत्र में कार्य करता है, तो उसकी उत्पादकता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए करियर का चयन केवल आर्थिक नहीं,बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से भी संतुलित होना चाहिए।

माइंडफुल करियर नैतिक मूल्यों पर भी बल देता है। सफलता तभी सार्थक है जब वह ईमानदारी,जिम्मेदारी और सामाजिक संवेदनशीलता के साथ प्राप्त की जाए। आज के समय में कंपनियाँ केवल तकनीकी दक्षता नहीं,बल्कि नेतृत्व क्षमता,सहयोग,समस्या समाधान, संचार कौशल और नैतिक आचरण को भी महत्व देती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को केवल परीक्षा की तैयारी नहीं,बल्कि व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देना चाहिए।

यह भी समझना आवश्यक है कि करियर कोई एक बार लिया गया निर्णय नहीं है। जीवन में परिस्थितियाँ बदलती हैं,रुचियाँ विकसित होती हैं और नए अवसर सामने आते हैं। ऐसे में करियर बदलना,नई पढ़ाई करना या नया कौशल सीखना असफलता नहीं, बल्कि विकास का संकेत है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है,वही भविष्य में अधिक सफल होता है।

अंततः,माइंडफुल करियर का अर्थ है अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करना। यह भीड़ का अनुसरण करने के बजाय अपनी पहचान बनाने की यात्रा है। जब करियर का चुनाव उद्देश्य, आत्मविश्वास, सीखने की इच्छा और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ किया जाता है, तब सफलता केवल पद या वेतन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन में संतोष, सम्मान और सार्थकता भी लेकर आती है।

याद रखिए,सही करियर वह नहीं जो सबसे अधिक पैसा दे,बल्कि वह है जो आपकी प्रतिभा को निखारे,आपके मूल्यों से मेल खाए और आपको हर दिन बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करे।

दो पीढ़ियों और जीवनसाथी के मध्य बेहतर समन्वय ही युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी परीक्षा

दुर्गेश्वर राय

जीवन की यात्रा जब अपने मध्य पड़ाव पर पहुँचती है,तब मनुष्य एक ऐसे संवेदनशील मोड़ पर खड़ा होता है जहाँ उसे पीछे छूटती और आगे बढ़ती, दोनों दिशाओं को एक साथ संभालना होता है। यही वह घड़ी है जो युवा पीढ़ी की वास्तविक परीक्षा लेती है। इस मोड़ पर खड़े व्यक्ति को एक ओर अपने बुजुर्ग माता-पिता की अपेक्षाओं, भावनाओं और ढलते स्वास्थ्य का संबल बनना होता है,तो दूसरी ओर अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य, संस्कारों और उनकी आधुनिक आकांक्षाओं को संवारना पड़ता है। दो पीढ़ियों के बीच संतुलन साधने की यह चुनौती केवल समय प्रबंधन का विषय नहीं है, बल्कि यह धैर्य, संवेदना और परिपक्वता का महायज्ञ है। जिसने इस मोड़ पर सही सामंजस्य स्थापित कर लिया,उसका जीवन वस्तुतः सफल माना जाता है, क्योंकि परिवार रूपी वृक्ष की जड़ें उसकी नींव पर टिक जाती हैं।

इस जटिल और बहुआयामी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ जीवनसाथी होता है। माता-पिता और बच्चों के बीच संतुलन साधने की यह पूरी यात्रा अधूरी और अत्यधिक कठिन हो जाती है यदि जीवनसाथी के साथ अटूट तालमेल,आपसी समझ और परस्पर सम्मान न हो। जीवनसाथी केवल एक सहभागी नहीं,बल्कि पूरे परिवार के भावात्मक ढांचे की रीढ़ होता है। जब दोनों एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हैं,एक-दूसरे की थकान और मानसिक दबाव का सम्मान करते हैं,तब दो पीढ़ियों को संभालने का यह दुर्गम कार्य सहज आनंद में बदल जाता है। यदि कोई अपने जीवनसाथी की भावनाओं, उसके त्याग और गृहस्थी के प्रति उसके योगदान को अनदेखा करता है,या परिवार की परंपराओं और बुजुर्गों की सेवा को बोझ माना जाने लगता है,तो घर का संतुलन पूरी तरह डगमगा जाता है। इसके विपरीत,जहाँ जीवनसाथी के बीच अटूट वैचारिक तालमेल होता है, वहाँ माता-पिता को भी पूर्ण सम्मान मिलता है और बच्चों को भी एक शांत,सुरक्षित और सुसंस्कृत वातावरण प्राप्त होता है। माता-पिता, जीवनसाथी और बच्चों के बीच का यह सेतु बनना कोई साधारण काम नहीं है। एक ओर माता-पिता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के निर्माण में खपा दिया। ढलती उम्र में उन्हें केवल भौतिक सुविधाओं की नहीं,बल्कि अपनों के स्पर्श,आत्मीयता और सम्मान की आवश्यकता होती है। कई बार उनके विचारों में पुरानी परिपाटी का आग्रह होता है,जो आधुनिक दौर की गति से मेल नहीं खाता। वहीं दूसरी ओर बच्चे हैं,जो असीम संभावनाओं और डिजिटल युग की तीव्र गति के साथ बड़े हो रहे हैं। उनकी सोच, उनकी जरूरतें और उनके सपने पूरी तरह से अलग हैं।

नागपंचमी,विष से अमृत तक,सर्प संस्कृति और भारतीय अध्यात्म की यात्रा

डॉ. मुश्ताक अहमद
हरदा,मध्यप्रदेश

हमारी प्राचीन परंपराएं मात्र रीति-रिवाजों या कर्मकांडों का संग्रह नहीं हैं, बल्कि वे अस्तित्व के विज्ञान और ब्रह्मांडीय संतुलन के गहरे दर्शन पर आधारित हैं। आधुनिक युग में जहां पर्यावरण और मनुष्य के बीच एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो चुकी है,वहीं हमारे पर्व हमें हमारी मूल जड़ों और सह-अस्तित्व की भावना से जोड़ते हैं। श्रावण मास में मनाया जाने वाला नागपंचमी का पर्व इसी चेतना का सबसे जीवंत और सुंदर प्रतीक है। यह पर्व केवल एक जीव विशेष की पूजा नहीं है,बल्कि यह संपूर्ण प्रकृति के प्रति अगाध कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक आध्यात्मिक और दार्शनिक उत्सव है।

आध्यात्मिक दृष्टि से सर्प को केवल एक साधारण जीव नहीं माना गया,बल्कि इसे चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक कहा गया है। मानव शरीर के भीतर स्थित मूल ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, जिसे सोते हुए सर्प के रूप में दर्शाया जाता है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है,तो मनुष्य भौतिक सीमाओं को लांघकर उच्च चेतना की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार,देवाधिदेव महादेव के गले में नाग का सुशोभित होना यह संदेश देता है कि प्रकृति के सबसे भयानक और विषैले तत्त्व भी यदि नियंत्रण में हों,तो वे संतुलन और सुंदरता का हिस्सा बन सकते हैं। यह भय और नियंत्रण का नहीं,बल्कि पूर्ण स्वीकार और सामंजस्य का प्रतीक है।

श्रावण मास वर्षा ऋतु का समय होता है। इस काल में धरती जलमग्न होती है, जिससे भूमि के भीतर रहने वाले जीव-जंतु अपने बिलों से बाहर आने के लिए विवश होते हैं। एक समय था जब मनुष्य सर्पों के विष और उनके भय के कारण उनसे घृणा या संहार कर सकता था। लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें भय को हिंसा में बदलने के बजाय आस्था और सम्मान में बदलने की कला सिखाई। नागपंचमी का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि इस पृथ्वी पर केवल मनुष्यों का ही अधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है।

अध्यात्म का मूल आधार अहिंसा और करुणा है। नागपंचमी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध अधिकार का नहीं,बल्कि सहभागिता का होना चाहिए। जहां मनुष्य अन्य जीवों को नष्ट करने के बजाय उनके अस्तित्व को स्वीकार करता है, वहीं वास्तविक आध्यात्मिकता का जन्म होता है। जब हम नाग देवता की पूजा करते हैं,तो हम प्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि प्रकृति की हर रचना का अपना एक प्रयोजन है। यह पर्व मनुष्य के अहंकार को तोड़कर उसे यह सिखाता है कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं,बल्कि उसका एक विनम्र संरक्षक मात्र है।

आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक असंतुलन और जैव-विविधता के संकट से जूझ रही है, तब हमारी परंपराएं हमें रास्ता दिखाने के लिए सबसे मजबूत स्तंभ हैं। नागपंचमी केवल एक पौराणिक कथा या पर्व नहीं है,बल्कि यह जीयो और जीने दो के शाश्वत सिद्धांत की पुनरावृत्ति है। यह पर्व हमें आमंत्रित करता है कि हम अपनी भयमुक्त और करुणा से भरी दृष्टि को अपनाएं, ताकि मनुष्य और प्रकृति मिलकर इस अस्तित्व के संगीत को सुरीला और निरंतर बनाए रख सकें।

मक्का की डील से बदलेगा पश्चिम एशिया या फिर यह सिर्फ कागजी गठबंधन साबित होगा?

अजय कुमार
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

मक्का में सऊदी अरब,तुर्किए और पाकिस्तान के बीच हुआ संयुक्त रक्षा समझौता सिर्फ तीन देशों की सैन्य साझेदारी नहीं है। यह उस पश्चिम एशिया की बदलती तस्वीर का संकेत है,जहां पुराने सुरक्षा समीकरण तेजी से टूट रहे हैं और नए शक्ति-केंद्र आकार ले रहे हैं। समझौते की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि तीनों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला बाकी दोनों पर हमला माना जाएगा। कागज पर यह व्यवस्था बेहद मजबूत दिखती है,लेकिन असली सवाल यह है कि युद्ध की घड़ी आने पर क्या रियाद,अंकारा और इस्लामाबाद एक-दूसरे के लिए अपने सैनिक और अपनी अर्थव्यवस्था जोखिम में डालेंगे? इसी सवाल में इस समझौते की असली कहानी छिपी है। इसे तुरंत 'इस्लामिक नाटो' कहना जल्दबाजी होगी। नाटो की ताकत केवल इस बात में नहीं है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है,बल्कि उसके पीछे दशकों से विकसित संयुक्त कमान, सैन्य योजना,खुफिया ढांचा,अंतर-संचालन और साझा रक्षा प्रतिबद्धताएं हैं। मक्का समझौते में फिलहाल ऐसी संस्थागत गहराई दिखाई नहीं देती। इसलिए इसे नाटो की प्रतिकृति कहने के बजाय तीन देशों के बीच सामरिक प्रतिरोध बढ़ाने की कोशिश कहना ज्यादा सही होगा। फिर भी इसे हल्का समझना भी बड़ी भूल होगी। तीनों देशों की ताकतें अलग-अलग हैं और यही इस गठबंधन की सबसे बड़ी उपयोगिता है। तुर्किए के पास तेजी से विकसित होता रक्षा उद्योग, ड्रोन तकनीक और बड़ा सैन्य ढांचा है। सऊदी अरब के पास विशाल वित्तीय संसाधन और ऊर्जा संपदा है।

पाकिस्तान के पास दशकों का सैन्य अनुभव,बड़ी स्थायी सेना और परमाणु क्षमता है। 2025 में तुर्किए का सैन्य खर्च करीब 30 अरब डॉलर, पाकिस्तान का 11.9 अरब डॉलर और सऊदी अरब का 83.2 अरब डॉलर रहा। उसी साल भारत का सैन्य खर्च 92.1 अरब डॉलर था। यानी तीनों देशों की सैन्य क्षमताएं जोड़ने पर तस्वीर गंभीर जरूर बनती है, लेकिन इसे एकीकृत सैन्य शक्ति समझ लेना अभी गलत होगा।

सबसे दिलचस्प पक्ष सऊदी अरब है। रियाद वर्षों तक अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है। लेकिन पश्चिम एशिया के लगातार बदलते समीकरणों ने सऊदी नेतृत्व को यह समझा दिया है कि केवल अमेरिकी सुरक्षा छतरी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। ईरान के साथ तनाव, यमन में हूती खतरा,लाल सागर की अस्थिरता और तेल प्रतिष्ठानों पर संभावित हमले ने सऊदी सुरक्षा सोच को बदल दिया है। इसलिए पाकिस्तान और तुर्किए के साथ सुरक्षा सहयोग रियाद के लिए वैकल्पिक सुरक्षा परत तैयार करने का प्रयास भी है। लेकिन यहीं पहला विरोधाभास सामने आता है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा हित युद्ध जीतना नहीं, स्थिरता बनाए रखना है। उसका पूरा आर्थिक परिवर्तन कार्यक्रम तेल से आगे निकलकर पर्यटन, निवेश, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर टिका है। लंबी क्षेत्रीय जंग उसके इस एजेंडे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अगर कभी पाकिस्तान या तुर्किए ऐसा संघर्ष शुरू करते हैं जिसमें सऊदी हित सीधे शामिल नहीं हैं,तो क्या रियाद वास्तव में सैन्य हस्तक्षेप करेगा? समझौते की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी। तुर्किए का मामला और जटिल है। अंकारा की विदेश नीति किसी एक खेमे में पूरी तरह बंधी हुई नहीं रही है। वह नाटो का सदस्य है, लेकिन रूस के साथ भी उसके रिश्ते हैं। सीरिया, लीबिया, कॉकस और पूर्वी भूमध्यसागर में उसके अपने रणनीतिक हित हैं। तुर्किए सऊदी अरब के साथ संबंध सुधार चुका है,लेकिन दोनों देशों की क्षेत्रीय प्राथमिकताएं हमेशा एक जैसी नहीं रहीं। इसलिए अंकारा किसी ऐसे युद्ध में अपने सैनिक झोंकने से पहले दस बार सोचेगा जिसमें उसके प्रत्यक्ष राष्ट्रीय हित दांव पर न हों।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

CMYK

85 किमी की आस्था यात्रा पर निकले कांवरिये,41 साल से चली आ रही परंपरा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
सावन शुरू होते ही सरगुजा में 41 साल पुरानी कांवर यात्रा की परंपरा फिर जीवंत हो गई। शनिवार को शंकरघाट स्थित बांक नदी से हजारों कांवरियों ने जल उठाया और करीब 85 किलोमीटर की पदयात्रा पर कैलाश गुफा के लिए रवाना हुए। यहां पहुंचकर कांवरिये भगवान कैलाशनाथेश्वर का जलाभिषेक करेंगे। शनिवार सुबह शंकरघाट से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों तक बोलबम और हर-हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे। सरगुजा कांवरिया सेवा संघ के तत्वावधान में निकाली जाने वाली इस यात्रा में सरगुजा के अलावा कोरिया, रायगढ़, जशपुर और सीमावर्ती राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचे। कांवरियों का आना शुक्रवार दोपहर से ही शुरू हो गया था। मध्यरात्रि के बाद करीब एक बजे से शंकरघाट में बांक नदी से जल उठाने के लिए भीड़ जुटने लगी। बड़ी संख्या में कांवरियों ने रात में शंकरघाट में ही विश्राम किया। शनिवार सुबह कांवरिये नाचते-गाते और जयघोष करते हुए कैलाश गुफा के लिए रवाना हुए। यात्रा में महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल रहे। कई जत्थे सूर्योदय से पहले ही शहर से आगे निकल गए। अंबिकापुर से बतौली तक सड़क पर कांवरियों का रेला दिखाई दिया।

रास्ते में सेवा,जगह-जगह स्वागत

कांवरियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर विभिन्न संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने जलपान, पेयजल और नाश्ते की व्यवस्था की। जगह-जगह कांवरियों का स्वागत भी किया गया। यात्रा के दौरान विभिन्न संगठनों ने भगवान शिव-पार्वती और गणेश की जीवंत झांकियां भी निकालीं,जो आकर्षण का केंद्र रहीं।

सुरक्षा के लिए प्रशासन ने संभाली व्यवस्था : कांवर यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। अधिकारियों की मजिस्ट्रियल ड्यूटी लगाई गई थी। शंकरघाट से शुरू हुई यात्रा लुचकी, चेंद्रा और लमगांव होते हुए देर शाम बतौली पहुंची। यहां विश्राम के बाद कांवरियों का जत्था कैलाश गुफा के लिए रवाना होगा।

जन्म के पहले घंटे में स्तनपान जरूरी छः माह तक केवल मां का दूध

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय,अंबिकापुर के प्रसूति एवं स्त्री रोग तथा शिशु रोग विभाग की ओर से जागरूकता एवं परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं, नवप्रसूता माताओं और उनके परिजनों को स्तनपान,नवजात के पोषण और मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बताया कि बच्चे के जन्म के पहले एक घंटे के भीतर स्तनपान कराना उसके स्वस्थ जीवन की महत्वपूर्ण शुरुआत है। जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलोस्ट्रम नवजात के लिए प्राकृतिक पहला टीका है। यह उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में मदद करता है। चिकित्सकों ने माताओं से कहा कि बच्चे को जन्म से छः माह तक केवल मां का दूध ही दें। इस दौरान बच्चे को पानी या अन्य कोई आहार देने की आवश्यकता नहीं है। माताओं को स्तनपान की सही विधि, उचित मुद्रा, स्तनों की देखभाल और संतुलित व पौष्टिक आहार के संबंध में भी जानकारी दी गई। चिकित्सकों ने कहा कि मां का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। गर्भावस्था के साथ स्तनपान अवधि में भी आयरन और कैल्शियम का सेवन, नियमित स्वास्थ्य जांच और समस्या होने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की गई। कार्यक्रम में पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी स्तनपान के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं ने नवजात की

देखभाल और स्तनपान से संबंधित सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञ चिकित्सकों ने समाधान किया। इस अवसर पर संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉ. आरसी आर्या, सिविल सर्जन डॉ. जेके रेलवानी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अविनाशी कुजूर, शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. केआर टेकाम सहित चिकित्सक, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ तथा बड़ी संख्या में गर्भवती और नवप्रसूता माताएं उपस्थित थीं।

शादी के चार दिन बाद दुल्हन गायब वापस लाने पहुंचे तो मांगे 50 हजार

-संवाददाता-
लखनपुर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
लखनपुर थाना क्षेत्र के जमगला में शादी के नाम पर कथित ठगी का मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश निवासी रामकली बाई ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे की शादी के बाद दुल्हन महज तीन दिन ससुराल में रही और चौथे दिन रात में शौचालय जाने की बात कहकर घर से चली गई। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद जब वे दुल्हन को

वापस लाने पहुंचे तो उनसे 50 हजार रुपए की अतिरिक्त मांग की गई। रामकली बाई ने मामले की शिकायत 6 अगस्त को लखनपुर थाने में की थी। वहां सुनवाई नहीं होने एसपी को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार रामकली बाई के बेटे तुलसीदास लोधी का विवाह 23 मई 2026 को जमगला निवासी युवती से हुआ था। विवाह कराने में जमगला निवासी दो मध्यस्थों की भूमिका बताई गई है। आरोप है कि शादी के दौरान दूल्हे पक्ष से एक लाख रुपए नकद और करीब एक लाख रुपए के जेवरात लिए गए थे। शादी के बाद दुल्हन तीन दिन तक ससुराल में रही। चौथे दिन रात में वह शौचालय जाने की बात कहकर घर से चली गई और वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उसे चुपके से अपने साथ ले गए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पूरी घटना सुनियोजित तरीके से की गई ठगी है, जिससे परिवार को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी हुई। पीड़ित पक्ष ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करने, नकदी और जेवर वापस दिलाने की मांग की है।

उदयपुर के पहाड़ी गांवों में मलेरिया का कहर,39 मरीज मिले पॉजिटिव

-संवाददाता-
उदयपुर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
विकासखंड उदयपुर के पहाड़ी और दूरस्थ गांवों में मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 39 मरीजों में प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम (पीएफ) मलेरिया की पुष्टि हो चुकी है। मरीजों में बड़ी संख्या में पहाड़ी कोरवा और पंडो जनजाति के लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांवों में मलेरिया नियंत्रण और रोकथाम के लिए सघन अभियान शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मतरिंगा,खर्रानगर,मुसरडांड,

मुकना पहाड़, बारो पहाड़,बकोई और सेमी घोघरा में मलेरिया के मरीज मिले हैं। इनमें मतरिंगा, मुसरडांड और खर्रानगर क्षेत्र में मलेरिया के मामले अधिक सामने आए हैं। 26 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट में 31 मरीजों के पॉजिटिव होने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। मरीजों की सूची में डेढ़ वर्ष के बच्चे से लेकर 60 वर्ष की महिला तक शामिल हैं। बच्चों, किशोरों और वयस्कों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। दस्तावेज के अनुसार मरीजों की पुष्टि 6 मई से अब तक अलग-अलग तिथियों में हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित गांवों में घर-घर जाकर बुखार से पीड़ित लोगों का सर्वे कर रही हैं।

छात्राओं को सड़क सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी के प्रति किया जागरूक

थाना प्रभारी ने यातायात नियमों के पालन के साथ ऑनलाइन ठगी से बचने के बताए उपाय

-संवाददाता-
लखनपुर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों के पालन और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,लखनपुर के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थाना लखनपुर के थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार की ओर से पुलिस अधिकारियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरक्षक दशरथ राजवाड़े ने छात्राओं को सुरक्षित यातायात के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में

होने वाली जान-माल की क्षति का एक प्रमुख कारण यातायात नियमों की अनदेखी है। प्रत्येक नागरिक यदि यातायात नियमों का पालन करे तो सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी लाई जा सकती है। उन्होंने छात्राओं को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का इंश्योरेंस रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि छात्राएं स्वयं यातायात नियमों का पालन करने के साथ अपने परिवार के सदस्यों और परिचितों को भी नियमों के पालन के लिए प्रेरित करें। पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति भी सचेत किया। उन्होंने कहा कि शराब, तंबाकू, गुटखा और अन्य मादक पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ परिवार और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की अपील की गई।

फर्जी कॉल और डिजिटल अरेस्ट से रहें सावधान : कार्यक्रम में छात्राओं को ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने फर्जी फोन कॉल, लॉटरी का लालच, बैंक अधिकारी बनकर गोपनीय जानकारी मांगना, ओटीपी हासिल करना तथा डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और सोशल मीडिया पर आने वाले फर्जी संदेशों तथा आकर्षक ऑफरों के झांसे में न आएं। किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने और साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। इस दौरान छात्राओं ने साइबर अपराध, यातायात नियमों और सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे, जिनका पुलिस अधिकारियों ने समाधान किया।

कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने, नशे से दूर रहने और साइबर अपराधों के प्रति सजग रहने का संकल्प दिलाया गया। विद्यालय की प्राचार्य रंजना श्रीवास्तव ने भी छात्राओं को सड़क सुरक्षा एवं साइबर सिक्योरिटी के प्रति सतर्क रहने की अपील की। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

प्रशासन निकले हैं गौधाम भूमि निरीक्षण में...मवेशी मयखाने में शराब मांगने नहीं आये हैं...

मतलबी पलकों के बेरूखी से आशियाना के तलाश में खड़े हैं

-संवाददाता-
राजपुर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
बलरामपुर जिले के राजपुर प्रशासक प्रशासनिक अमला के साथ शासन की नई गो गोधाम योजना के लिए भूमि निरीक्षण करने की खबरें देखी जा रही है वहीं दूसरी और राजपुर के शराब दुकान के पास चीखने की दुकान के बगल में पलकों की बेरुखी के कारण मवेशी बरसात में आशियाने की तलाश में खड़े हैं। इनकी जिम्मेदार कौन? अजीब विडम्बना है छत्तीसगढ़ में सरकारे बदलने के

बाद से देखा जा रहा है आवारा मवेशियों के लिए भाजपा शासन के द्वारा पलकों के द्वारा आवारा बनाए गए मवेशियों के गौ सेवा सदन के नाम पर लाखों लाखों रुपए का बजट बनाकर योजना के तहत आवारा बनाए गए मवेशियों के लिए अधिग्रहण कर गौ सेवा सदन के नाम पर महानगरों में आशियाना बनाया गया था,उक्त आशियाना में मवेशियों के देखभाल के लिए संचालक से लेकर मजदूरों की नियुक्ति की गई थी उनके लिए बजट के अनुसार आचार्य पानी से लेकर मृत्यु उपरांत मवेशियों को अग्नि देने मवेशी आशियाने की तलाश में भटकते नजर आते थे आज गौ सेवा सदन की भूमि का कोई अता पता नहीं। सरकार बदलने के बाद जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो नरवा गरवा बड़ी के तहत प्रदेश के समस्त पंचायत में करोड़ों खर्च करने की बात भी फलों के द्वारा बनाए गए आवारा पशुओं के लिए कोई गौशाला नहीं बचा है। वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा गौधाम योजना के तहत जिले के राजपुर एसडीएम देवेंद्र प्रधान प्रशासनिक अमला को लेकर गौधाम के लिए के लिए भूमि निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं नगर पंचायत क्षेत्र राजपुर के शराब दुकान के बगल में बने चिखना दुकान के बगल में खड़े पालकों के द्वारा आवारा मवेशी बारिश में आशियाना की तलाश में खड़े नजर आ रहे हैं।

आयुष चिकित्सकों पर दबाव के आरोप को बताया निराधार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ आयुर्वेद अधिकारी संघ ने परिषद चुनाव 2026 में आयुष चिकित्सकों पर मतदान के लिए दबाव बनाए जाने के आरोपों का खंडन किया है। संघ ने कहा कि प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सक अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। संघ के अनुसार छत्तीसगढ़ आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद,रायपुर के चुनाव में प्रदेश के प्रत्येक संभाग से अधिकृत प्रत्याशी मैदान में हैं। संघ का उद्देश्य आयुर्वेद एवं संबंधित चिकित्सा पद्धतियों के पंजीकृत चिकित्सकों के हितों को परिषद के समक्ष प्रभावी ढंग से रखना और परिषद के कामकाज में पारदर्शिता,निष्पक्षता व चिकित्सकों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. गदाधर पंडा ने कहा कि किसी भी आयुष चिकित्सक पर मतदान के लिए दबाव, भय, प्रलोभन या किसी तरह का अनुचित प्रभाव नहीं बनाया गया है। चिकित्सक अपनी इच्छा और विवेक के अनुसार मतदान कर सकते हैं।

मिनीमाता महतारी जतन योजना से लीलावती को मिला आर्थिक संबल

20 हजार की सहायता राशि से बच्चों के खान-पान और पालन-पोषण में मिलेगी मदद,मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रम विभाग द्वारा संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना श्रमिक परिवारों की जरूरतमंद माताओं के लिए आर्थिक सहारा बन रही है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से माताओं को बच्चों के खान-पान, देखभाल और पालन-पोषण से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत भिट्ठिकला के ढोढ़ीपारा निवासी श्रीमती लीलावती भी इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। श्रमिक के रूप में कार्य करने वाली लीलावती के दो बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक

स्थिति को देखते हुए बच्चों की जरूरतों को पूरा करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। ऐसे समय में योजना के तहत मिली 20 हजार रुपये की सहायता राशि उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। लीलावती ने बताया कि वह प्राप्त राशि का उपयोग बच्चों के खान-पान, देखभाल और बेहतर पालन-पोषण में करेंगी। आर्थिक सहायता मिलने से बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में उन्हें सहारा मिलेगा और परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम होगा। उन्होंने कहा कि श्रमिक परिवारों और माताओं के हित में संचालित सरकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही हैं। लीलावती ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योजना से मिली 20 हजार रुपये की सहायता उनके बच्चों के बेहतर पालन-पोषण और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मिनीमाता महतारी जतन योजना के माध्यम से श्रमिक परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर मातृत्व एवं शिशु देखभाल को मजबूत करने तथा जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में पहल की जा रही है।

शहर के विकास कार्यों की कलेक्टर ने ली ग्राउंड रिपोर्ट,धीमे काम पर जताई नाराजगी

नालंदा परिसर,चौक सौंदर्यीकरण,क्रिटिकल केयर ब्लॉक और बाकी नदी पुल का निरीक्षण,गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

-संवाददाता-
जशपुरनगर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
शहर में चल रहे विकास और निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने कलेक्टर रोहित व्यास शनिवार को मैदानी निरीक्षण पर निकले। उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र में निर्माणाधीन नालंदा परिसर,विभिन्न चौकों के सौंदर्यीकरण, सामुदायिक भवन के साथ जिला अस्पताल के समीप बन रहे 50 बेड के क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक और बाकी नदी पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कई कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को काम में तेजी लाने, गुणवत्ता से समझौता नहीं करने और तय समय-सीमा में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए।

11 करोड़ की लागत से बन रहा 500 सीटर नालंदा परिसर : कलेक्टर ने करीब 2.87 हेक्टेयर में 11 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 500 सीटर नालंदा परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की प्रगति की जानकारी लेकर काम तेज करने के निर्देश दिए। परिसर में आधुनिक लाइब्रेरी और डिजिटल अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए बेहतर अध्ययन वातावरण मिलेगा। जुदेव चौक के समीप करीब 64 लाख रुपए की लागत से हो रहे सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने धीमी गति पर नाराजगी जताई। यहां आकर्षक फव्वारा,सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राओं की प्रतिकृतियां सहित अन्य सौंदर्यीकरण कार्य किए जा रहे हैं।

सामुदायिक भवन और चौक भी होंगे आकर्षण का केंद्र : पुरानी टोली में करीब 74 लाख रुपए की लागत से बन रहे सामुदायिक भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। यहां फिनिशिंग का काम चल रहा है। कलेक्टर ने शेष कार्य जल्द पूरा करने कहा। भवन तैयार होने के बाद शासकीय कार्यक्रमों के साथ शादी-विवाह और सामाजिक आयोजनों के लिए नागरिकों को सुविधा मिलेगी। वहीं करीब 15 लाख रुपए की लागत से डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर चौक और बालासाहेब देशपांडे चौक में किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्यों को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि चौकों का बेहतर विकास शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ लोगों के लिए आकर्षण और प्रेरणा का केंद्र बनाएगा।

50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक जल्द होगा तैयार : कलेक्टर ने जिला अस्पताल के समीप 11 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे 50 बेड के क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का भी निरीक्षण किया। ग्राउंड फ्लोर सहित चार मंजिला भवन में गंभीर और जीवन-जोखिम वाले मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। वर्तमान में भवन में फिनिशिंग का काम चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित मानकों और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए शेष कार्य जल्द पूरा करने कहा। अस्पताल में मरीजों और परिजनों की सुविधा के लिए साइनेज और कलर कोडिंग,आईसीयू,ओटी और इमरजेंसी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग,व्यवस्थित वृक्षारोपण और लिफ्ट का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अस्पताल में पानी और बिजली की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल केयर जैसी संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बिजली और पानी की निरंतर उपलब्धता जरूरी है।

3.84 करोड़ का पुल जोड़ेगा जशपुर को गम्हरिया से : जशपुर नगर को गम्हरिया से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर बाकी नदी में करीब 3.84 करोड़ रुपए की लागत से 72 मीटर लंबे पुल का निर्माण चल रहा है। कलेक्टर ने पुल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। ब्रिटिश शासनकाल में बना पुराना पुल जर्जर होने के बाद उसके स्थान पर नया पुल बनाया जा रहा है। उन्होंने पुल निर्माण में गुणवत्ता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने कहा। साथ ही पुल और सड़क के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, सड़क किनारे आवश्यक सुरक्षा उपाय और दुर्घटनाओं की रोकथाम के प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.एस. जात्रा, सीजीएमएससी के एसडीओ ललित वर्मा, नगर पालिका के सहायक अभियंता कैलाश खरोले, उप अभियंता शुभेंदु श्रीवास्तव,सेतु निर्माण विभाग के एसडीओ मनोज मरकाम सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

CMYK

बैकुंठपुर पालिका चुनाव में भाजपा का नया चेहरा बन सकते हैं सीए प्रशांत गुप्ता!

बैकुंठपुर पालिका चुनाव में सीए प्रशांत गुप्ता के नाम की बढ़ी चर्चा,भाजपा के लिए बन सकते हैं नया चेहरा

भाजपा के पुराने चेहरों के बीच प्रशांत गुप्ता की दावेदारी ने बढ़ाई हलचल,क्या सीए को मिलेगा मौका?

बैकुंठपुर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा का नया प्रयोग? सीए प्रशांत गुप्ता का नाम चर्चा में सबसे आगे

क्या बैकुंठपुर को मिलेगा पढ़ा-लिखा चेहरा? भाजपा में सीए प्रशांत गुप्ता की दावेदारी पर मंथन

शैलेश-भानु-सुभाष-अनिल के बीच प्रशांत गुप्ता की एंट्री,भाजपा के सामने नए चेहरे पर दांव का सवाल

राजनीति से आगे विकास का पेशेवर मॉडल! बैकुंठपुर में सीए प्रशांत गुप्ता की संभावित दावेदारी चर्चा में...

शिक्षित, युवा और पेशेवर चेहरे की तलाश के बीच प्रशांत गुप्ता का नाम चर्चा में सबसे आगे,भाजपा के सामने पुराने चेहरों और नए नेतृत्व के बीच चयन की चुनौती

-रवि सिंह-

बैकुण्ठपुर 08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले की नगर पालिका राजनीति में जनवरी 2027 में होने वाले संभावित चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है, बैकुंठपुर और जिले की दूसरी नगर पालिका में चुनावी समीकरणों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के भीतर संभावित प्रत्याशियों के नामों पर मंथन शुरू हो गया है, बैकुंठपुर में अध्यक्ष पद अनारक्षित मुक्त रहने की स्थिति ने दावेदारों का दायरा और बढ़ा दिया है,भाजपा के सामने जहां पूर्व अध्यक्ष शैलेश शिवहरे, पूर्व उपाध्यक्ष भानु पाल, और पार्षद एवं मंडल अध्यक्ष अनिल खटीक जैसे अनुभवी नाम चर्चा में हैं, वहीं इस पूरी दौड़ में एक ऐसा नाम भी सामने आया है जो अपनी राजनीतिक पहचान से ज्यादा शैक्षणिक योग्यता, पेशेवर उपलब्धि और युवा चेहरे के कारण अलग दिखाई देता है-चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशांत गुप्ता, प्रशांत गुप्ता की संभावित दावेदारी को लेकर अभी भाजपा संगठन की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है,लेकिन राजनीतिक हलकों में उनके नाम की चर्चा लगातार बढ़ रही है, खासकर यदि पार्टी इस बार किसी नए, शिक्षित,पेशेवर और अपेक्षाकृत विवादमुक्त चेहरे पर दांव लगाने का निर्णय करती है,तो प्रशांत गुप्ता को संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

क्यों अलग है प्रशांत गुप्ता का चेहरा?

नगर पालिका चुनाव में किसी उम्मीदवार की राजनीतिक पकड़ के साथ-साथ उसकी व्यक्तिगत छवि,शिक्षा, सामाजिक संपर्क और शहर के विकास को लेकर उसकी सोच भी महत्वपूर्ण होती है,प्रशांत गुप्ता की दावेदारी की चर्चा इन्हीं अलग-अलग पहलुओं को जोड़कर की जा रही है,वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वित्तीय मामलों की समझ रखने वाले पेशेवर के रूप में उनकी पहचान है,उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने बैकुंठपुर के सरस्वती शिशु मंदिर से वर्ष 2005 में बारहवीं तक की शिक्षा पूरी की, इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी को अपने करियर का लक्ष्य बनाया और वर्ष 2010 में सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, बताया गया है कि उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 43 हासिल की,जो बैकुंठपुर जैसे क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धि मानी जा सकती है, यही उपलब्धि उन्हें पारंपरिक स्थानीय राजनीति के दावेदारों से अलग खड़ा करती है, यदि भाजपा नगर पालिका को केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि वित्तीय अनुशासन, बेहतर प्रबंधन, योजनाओं की प्राथमिकता और आधुनिक शहरी विकास के नजरिए से चलाने वाले चेहरे की तलाश करती है, तो प्रशांत गुप्ता का पेशेवर अनुभव उनके पक्ष में जा सकता है।

नगरपालिका के आर्थिक प्रबंधन में सीए की पृष्ठभूमि बन सकती है ताकत

नगर पालिका केवल राजनीतिक संस्था नहीं बल्कि एक स्थानीय प्रशासनिक एवं वित्तीय निकाय भी है। शहर में सड़क, नाली, पानी, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, भवन निर्माण,बाजार,पार्क और अन्य विकास कार्यों के साथ-साथ बजट प्रबंधन और विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि का उचित उपयोग भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है,ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पेशेवर पृष्ठभूमि रखने वाला चेहरा नगर पालिका के आर्थिक पक्ष को बेहतर तरीके से समझ सकता है—यह तर्क प्रशांत गुप्ता की संभावित दावेदारी के समर्थन में दिया जा रहा है,उनके पेशेवर कार्यक्षेत्र में कराधान,ऑडिट,वित्तीय परामर्श,बैंकिंग और परियोजना वित्त जैसे विषय शामिल बताए जाते हैं। यदि इस अनुभव को स्थानीय निकाय के कामकाज से जोड़ा जाए तो नगर पालिका की वित्तीय योजना,बजट प्राथमिकता और परियोजनाओं की व्यवहार्यता जैसे विषयों पर उनकी विशेषज्ञता उपयोगी साबित हो सकती है,हालांकि चुनावी राजनीति में केवल पेशेवर योग्यता जीत की गारंटी नहीं होती,उम्मीदवार का वार्ड स्तर पर जनसंपर्क,संगठन में स्वीकार्यता और मतदाताओं के बीच व्यक्तिगत प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है,प्रशांत गुप्ता के लिए भी यही सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगी।

राजनीतिक विरासत भी प्रशांत गुप्ता के पक्ष में- प्रशांत गुप्ता की चर्चा केवल उनके सीए होने के कारण नहीं हो रही है, उनके पीछे एक ऐसा परिवार भी है जिसकी बैकुंठपुर और कोरिया की राजनीतिक-सामाजिक गतिविधियों में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका रही है, उनके पिता स्वर्गीय रामधनी गुप्ता (गुल्लू गुप्ता) को क्षेत्र में भाजपा के पुराने और वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता था,उपलब्ध जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर 1954 को जन्मे रामधनी गुप्ता ने वर्ष 1977 में परिवहन व्यवसाय से अपने कार्यजीवन की शुरुआत की, इसके बाद उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की तथा बैकुंठपुर में युवा नेतृत्व के रूप में अपनी पहचान बनाई,भाजपा संगठन में उन्होंने विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई, वे भारतीय जनता युवा मोर्चा बैकुंठपुर के अध्यक्ष रहे। इसके बाद भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ में महामंत्री, कोरिया जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जैसे दायित्वों से जुड़े, सहकारिता और स्थानीय प्रशासन से जुड़े कार्यों में भी उनकी भूमिका रही। वे मार्केटिंग सोसायटी के अध्यक्ष रहे और नगर पालिका बैकुंठपुर में एल्डरमैन के रूप में भी कार्य किया, इस राजनीतिक विरासत का लाभ प्रशांत गुप्ता को कितना मिलेगा, यह चुनाव में ही तय होगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उनका परिवार भाजपा की स्थानीय राजनीति से अपरिचित नहीं रहा है।

पुराने नेताओं के बीच नया विकल्प बनने की संभावना- भाजपा के सामने इस बार एक दिलचस्प स्थिति है,एक ओर पूर्व अध्यक्ष शैलेश शिवहरे हैं, जिनके पास नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में काम करने का अनुभव और व्यापक सामाजिक संपर्क बताया जाता है,दूसरी ओर भानु पाल जैसे पुराने संगठनात्मक कार्यकर्ता हैं,और अनिल खटीक के नाम भी चर्चा में हैं,ऐसे में यदि पार्टी इन पुराने चेहरों में से किसी एक को चुनती है तो चुनाव की रणनीति अनुभव और स्थानीय राजनीतिक पकड़ पर आधारित होगी,लेकिन यदि संगठन यह महसूस करता है कि नगर पालिका के लिए एक नई राजनीतिक शुरुआत और नया चेहरा सामने लाया जाए, तो प्रशांत गुप्ता की दावेदारी स्वाभाविक रूप से मजबूत हो सकती है, विशेष रूप से भाजपा के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण होगा कि क्या वह नगर पालिका चुनाव में ऐसा चेहरा उतारना चाहती है जो सीधे पारंपरिक राजनीति से न आते हुए भी पार्टी की विचारधारा और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हो तथा अपनी पेशेवर पहचान के कारण शहर के शिक्षित और युवा मतदाताओं को आकर्षित कर सके।

'पढ़ा-लिखा चेहरा' बनाम 'जमीनी राजनीति' का सवाल

प्रशांत गुप्ता की दावेदारी के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नगर पालिका चुनाव में उनकी पेशेवर और शैक्षणिक उपलब्धियां जमीनी राजनीति में पर्याप्त राजनीतिक पूंजी में बदल सकती हैं? नगर पालिका चुनाव विधानसभा या लोकसभा चुनाव से अलग होता है। यहां मतदाता उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं,वार्ड की छोटी से छोटी समस्या, व्यक्तिगत संपर्क, सामाजिक रिश्ते और वर्षों से बनी राजनीतिक पहचान भी मतदान को प्रभावित करती है, यही कारण है कि प्रशांत गुप्ता के सामने यदि भाजपा टिकट देती है तो उन्हें अपनी पेशेवर पहचान के साथ-साथ वार्ड-दर-वार्ड मजबूत जनसंपर्क और संगठनात्मक नेटवर्क खड़ा करना होगा। उनके लिए यह चुनाव केवल पार्टी का टिकट पाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह साबित करने का अवसर होगा कि एक पेशेवर व्यक्ति स्थानीय राजनीति में भी उतनी ही प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

क्या भाजपा युवा चेहरे पर लगाएगी दांव?

भाजपा की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने की चर्चा लगातार होती रही है, बैकुंठपुर में भी यदि संगठन इस दिशा में आगे बढ़ता है तो प्रशांत गुप्ता जैसे चेहरे को अवसर मिलने की संभावना पर राजनीतिक चर्चा स्वाभाविक है, उनकी उम्र, पेशेवर योग्यता,परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि और आधुनिक शहरी विकास की संभावित सोच उन्हें अलग विकल्प बनाती है,हालांकि पार्टी के लिए केवल इन खूबियों के आधार पर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं होगा, उसे यह भी देखना होगा कि संगठन के भीतर उनकी स्वीकार्यता कितनी है और विभिन्न गुटों के बीच सहमति बनाने की क्षमता कितनी है। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है-प्रशांत गुप्ता की दावेदारी तभी वास्तविक राजनीतिक ताकत बनेगी जब भाजपा के भीतर उनके नाम पर व्यापक सहमति बन सके।

भाजपा के सामने गुटीय समीकरण भी चुनौती

बैकुंठपुर की स्थानीय राजनीति में अलग-अलग नेताओं के अपने प्रभाव क्षेत्र हैं, ऐसे में किसी एक चेहरे को टिकट मिलने के बाद दूसरे दावेदारों और उनके समर्थकों को साथ रखना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा, यदि प्रशांत गुप्ता को टिकट मिलता है तो भाजपा के सामने चुनौती होगी कि पुराने और अनुभवी दावेदारों को किस तरह साथ रखा जाए,यदि संगठन यह संतुलन बनाने में सफल रहता है तो नया चेहरा पार्टी के लिए चुनावी लाभ में बदल सकता है,लेकिन टिकट के बाद असंतोष पैदा हुआ तो यही दावेदारी चुनौती में भी बदल सकती है,इसलिए प्रशांत गुप्ता की संभावित दावेदारी का सबसे बड़ा सवाल केवल 'क्या वे योग्य हैं?' नहीं, बल्कि 'क्या भाजपा संगठन उनके नाम पर एकजुट हो सकता है?' भी होगा।

कांग्रेस की कमजोरी भाजपा की ताकत बन सकती है, लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं...

पिछले नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का लाभ भाजपा को मिला था और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष पद हासिल करने में सफल रही,इस बार कांग्रेस भी पिछली गलतियों से सबक लेकर मजबूत चेहरा उतारने की कोशिश करेगी,ऐसे में भाजपा के सामने सत्ता में होने का लाभ तो है,लेकिन सत्ता विरोधी भावनाओं और नगर पालिका के मौजूदा कार्यकाल को लेकर जनता की धारणा का भी सामना करना होगा,इस स्थिति में प्रत्याशी का व्यक्तिगत चेहरा और उसकी स्वीकार्यता महत्वपूर्ण हो सकती है,यही वह बिंदु है जहां प्रशांत गुप्ता जैसे अपेक्षाकृत नए चेहरे की उपयोगिता पर चर्चा होती है,यदि जनता के बीच स्थानीय स्तर पर किसी पुराने राजनीतिक विवाद से दूरी रखने वाला, शिक्षित और पेशेवर चेहरा प्रस्तुत करना पार्टी की रणनीति बनता है, तो वे भाजपा की पसंद बन सकते हैं।

अभी दावेदारी है,फैसला बाकी

फिलहाल प्रशांत गुप्ता की संभावित उम्मीदवारी को लेकर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है,इसलिए उन्हें भाजपा का प्रत्याशी मानना जल्दबाजी होगी,लेकिन संभावित दावेदारों के बीच उनका नाम जिस तरह चर्चा में है, वह निश्चित रूप से बैकुंठपुर की चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है, शैलेश शिवहरे के पास राजनीतिक अनुभव और जनसंपर्क है,भानु पाल के पास संगठनात्मक निष्ठा, सुभाष साहू के पास नगर पालिका का अनुभव, अनिल खटीक के पास संगठन और पार्षद की भूमिका-तो प्रशांत गुप्ता के पास युवा चेहरा, पेशेवर योग्यता और राजनीतिक विरासत का अलग संयोजन है,अब देखना यह होगा कि भाजपा इस बार अनुभव को प्राथमिकता देती है या नई पीढ़ी के चेहरे पर भरोसा करती है,यदि पार्टी की रणनीति युवा,शिक्षित,पेशेवर और अपेक्षाकृत नए चेहरे को आगे लाने की बनती है,तो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशांत गुप्ता निश्चित रूप से मजबूत विकल्प के रूप में सामने आ सकते हैं,लेकिन राजनीति में अंतिम निर्णय तक कुछ भी तय नहीं होता,टिकट वितरण से पहले समीकरण बदल सकते हैं,नए नाम सामने आ सकते हैं और दावेदारी का पूरा गणित भी बदल सकता है,इसलिए फिलहाल बैकुंठपुर की राजनीति में सबसे दिलचस्प सवाल यही है- क्या भाजपा इस बार नगर पालिका की कमान किसी अनुभवी राजनीतिक चेहरे को देगी,या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशांत गुप्ता के रूप में एक नए,शिक्षित और पेशेवर चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी?

वज्रपात के तीन घायलों को नहीं मिली 108,अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर भी नदारद

-संवाददाता-

लखनपुर 08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ग्राम केंवरी में घर के अंदर वज्रपात की चपेट में आने से घायल हुए तीन लोगों को परिजन पहले 108 एंबुलेंस के लिए परेशान होते रहे। एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने की बात कहे जाने के बाद निजी वाहन से घायलों को अस्पताल लाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी करीब आधे घंटे तक ड्यूटी डॉक्टर नहीं पहुंचे और एक ही स्टाफ नर्स तीनों घायलों की देखभाल करती रही। जानकारी के अनुसार केंवरी में एक घर में तीन लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान मौसम बदला और गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। अचानक घर के अंदर वज्रपात होने से तीनों घायल होकर बेहोश हो गए। परिजनों ने 108 संजीवनी एंबुलेंस को कई बार फोन किया, लेकिन एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने और अंबिकापुर से आने में समय लगने की जानकारी दी गई। इसके बाद परिजन निजी वाहन से तीनों को लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे।

आधे घंटे बाद पहुंचे ड्यूटी डॉक्टर :परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के समय तीनों घायल बेहोशी की हालत में थे,लेकिन मौके पर ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। एक स्टाफ नर्स ही तीनों मरीजों की देखभाल कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर के पहुंचने पर उपचार शुरू हुआ। फिलहाल उपचार के बाद तीनों की हालत स्थिर बताई जा रही है और वे खतरे से बाहर हैं।

बीएमओ बोले- रोस्टर के अनुसार रहती हैं दो नर्स : मामले में बीएमओ डॉ. ओपी प्रसाद ने कहा कि ओपीडी में सभी डॉक्टर मौजूद रहते हैं और आपातकालीन स्थिति में भी डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। यदि किसी समय कोई डॉक्टर नहीं मिल पाता तो दूसरे डॉक्टर मरीज का उपचार करते हैं। एंबुलेंस के संबंध में उन्होंने कहा कि 108 की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन संभव है कि उस समय एंबुलेंस किसी अन्य स्थान पर गई हो। स्टाफ नर्स की कमी के आरोप पर बीएमओ ने कहा कि रोस्टर के अनुसार प्रत्येक शिफ्ट में दो स्टाफ नर्स की ड्यूटी रहती है। संभव है कि उस समय एक नर्स प्रसव कार्य में व्यस्त रही हो। उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति की स्थिति में इसकी जानकारी के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

सीएमएचओ ने जांच के दिए निर्देश : मामले को लेकर सीएमएचओ डॉ. पीएस मार्को ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। घटना ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर आपात स्थिति में एंबुलेंस की उपलब्धता और अस्पताल में तत्काल चिकित्सकीय सेवा नहीं मिलने को लेकर परिजनों ने नाराजगी जताई है। अब स्वास्थ्य विभाग की जांच में ही स्पष्ट होगा कि घटना के समय अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और एंबुलेंस की वास्तविक स्थिति क्या थी।

भलौर में विवाहिता की फांसी से मौत पर गहराया संदेह

मायके पक्ष ने कहा...यह आत्महत्या नहीं,हत्या की आशंका

30 वर्षीय निशा जायसवाल की मौत के बाद कई सवालों के घेरे में घटनास्थल,सास पर मारपीट पति पर प्रताड़ना व गला दबाने के आरोप,सरकारी अनुदान की राशि को लेकर भी विवाद का दावा

फांसी या हत्या? निशा की मौत में गले और पीठ के निशान ने बढ़ाया रहस्य

निशा की मौत पर सवालों का घेरा, पंखे से बंधा दुपट्टा और शरीर पर चोट के निशान

फंदे से पहले क्या हुआ? निशा की मौत में गले के निशान और पीठ की चोट बनी जांच की कड़ी

-रवि सिंह-

एमसीबी/मनेन्द्रगढ़,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। विवाहिता निशा जायसवाल की मौत का मामला अब केवल फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की घटना तक सीमित नहीं रह गया है,मृतिका के मायके पक्ष द्वारा सामने लाई गई तस्वीरों और घटनास्थल से जुड़े सवालों ने मौत की परिस्थितियों को लेकर संदेह और गहरा कर दिया है, परिजनों ने निशा के शरीर पर पीठ सहित अन्य स्थानों पर चोट के निशान होने का दावा करते हुए हत्या की आशंका जताई है,मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल गले पर दिखाई दे रहे निशान, पीठ पर चोट के कथित निशान और पंखे से जुड़े दुपट्टे को लेकर उठाया जा रहा है,परिजनों का कहना है कि यदि निशा ने पंखे से दुपट्टे के सहारे फांसी लगाई थी तो घटनास्थल की पूरी परिस्थितियों और शरीर पर मौजूद निशानों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाना चाहिए।

बता दे की मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत भलौर में 30 वर्षीय विवाहिता निशा जायसवाल की फांसी लगाकर मौत के मामले में अब मायके पक्ष के आरोपों के बाद घटना ने नया मोड़ ले लिया है,उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से पहुंचे मृतका के परिजनों ने सिटी कोतवाली में शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है,परिजनों ने मौत को सामान्य आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना, मारपीट और पैसों की मांग किए जाने के आरोप लगाए हैं,साथ ही मृतका के शरीर पर चोट के निशान होने तथा घटनास्थल की परिस्थितियों को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई गई है, मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृतका का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलने के बजाय नीचे पलंग पर मिलने की बात मायके पक्ष ने कही है,इसी के साथ गले पर निशान और मौके पर बेल्ट पड़े होने का दावा भी किया गया है,हालांकि इन सभी बिंदुओं की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, मौत की वास्तविक वजह क्या है,यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट,फॉरेंसिक जांच,घटना स्थल से जुटाए गए साक्ष्यों और पुलिस विवेचना के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

पति पर मारपीट और गला दबाने के गंभीर आरोप-मृतका के भाई ने अपने आरोपों में पति नीरज जायसवाल पर भी कथित मारपीट और गला दबाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं,मायके पक्ष का कहना है कि निशा को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था और पैसों को लेकर भी दबाव बनाया जाता था,हालांकि पति या ससुराल पक्ष का इस संबंध में क्या पक्ष है,यह अभी सामने नहीं आया है,पुलिस के लिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि मृतिका के साथ पूर्व में किसी प्रकार की मारपीट या प्रताड़ना की शिकायत हुई थी या नहीं।

शरीर पर चोट के निशान को लेकर भी सवाल-मायके पक्ष ने निशा के शव को देखने के बाद उसके शरीर पर कई स्थानों पर चोट अथवा चोट जैसे निशान होने का दावा किया है। परिजनों के अनुसार पीठ पर काले धब्बे जैसा निशान दिखाई दिया,जिसे वे बेल्ट से मारने का संभावित निशान मान रहे हैं,इसी तरह चेहरे और आंख के नीचे भी चोट अथवा कालापन दिखाई देने का दावा किया गया है,परिजनों का कहना है कि इन निशानों की भी जांच होनी चाहिए,लेकिन इन निशानों की प्रकृति और उनके कारण के बारे में अंतिम निष्कर्ष केवल देखकर नहीं निकाला जा सकता,पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक की रिपोर्ट तथा आवश्यकता पड़ने पर फॉरेंसिक परीक्षण से यह पता चल सकेगा कि शरीर पर मौजूद निशान मृत्यु से पहले के हैं, मृत्यु के बाद के हैं अथवा किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए हैं।

पांच वर्ष पहले हुई थी शादी,दो छोटी बच्चियां भी हैं...

मृतका के भाई वीरेंद्र जायसवाल के अनुसार निशा की शादी करीब पांच वर्ष पहले नीरज जायसवाल,पिता सुरेश जायसवाल के साथ हुई थी,शादी के बाद से ही निशा को कथित रूप से परेशान किए जाने की बात मायके पक्ष ने कही है, परिजनों का कहना है कि निशा के वैवाहिक जीवन को लेकर पहले भी परिवार के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती थी और पैसों की मांग किए जाने की शिकायतें सामने आती रही थीं,निशा की दो छोटी बच्चियां हैं,जिसके कारण उसकी मौत ने परिवार को और अधिक गहरे संकट में डाल दिया है,मायके पक्ष का आरोप है कि यदि वैवाहिक जीवन में प्रताड़ना और आर्थिक दबाव की स्थिति थी तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि घटना से पहले मृतका किन परिस्थितियों से गुजर रही थी।

मौत से दो दिन पहले मां को फोन करने का दावा

मामले में एक अहम कड़ी मृतका की अपनी मां से हुई कथित फोन बातचीत को बताया जा रहा है,भाई वीरेंद्र जायसवाल के अनुसार 6 अगस्त को निशा ने अपनी मां को फोन कर बताया था कि उसकी सास ने उसकी छाती पर लात मारी है,मायके पक्ष का कहना है कि यह बातचीत घटना से कुछ समय पहले हुई थी और इसके करीब दो दिन बाद उन्हें निशा की मौत की सूचना मिली, ऐसे में परिजनों का सवाल है कि मौत से पहले निशा के साथ घर में क्या हुआ था और क्या उस समय किसी प्रकार का विवाद या मारपीट हुई थी? इस फोन बातचीत की वास्तविकता,समय और उसमें कही गई बातों की पुष्टि पुलिस जांच के दौरान कॉल डिटेल, उपलब्ध रिकॉर्ड अथवा अन्य साक्ष्यों के आधार पर की जा सकती है।

फंदा,गले का निशान और पलंग पर शव...तीन बिंदु जांच के केंद्र में...

मायके पक्ष ने घटनास्थल को लेकर सबसे गंभीर सवाल शव की स्थिति को लेकर उठाया है,परिजनों के मुताबिक यदि निशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की तो शव फंदे पर लटका हुआ क्यों नहीं मिला? उनका दावा है कि मृतका का वजन करीब 60 किलो था और शव नीचे पलंग पर लिटा हुआ मिला,इसके अलावा मौके पर गले के निशान के साथ एक बेल्ट पड़े होने की बात भी परिजनों ने कही है,यही कारण है कि मायके पक्ष यह सवाल उठा रहा है कि यदि शव फंदे से उतारा गया था तो उसे किसने उतारा,कब उतारा और पुलिस के पहुंचने से पहले उसे पलंग पर क्यों रखा गया? इन सवालों का उत्तर घटनास्थल के वैज्ञानिक परीक्षण से ही मिल सकता है,पुलिस को यह भी देखना होगा कि जिस स्थान पर कथित रूप से फांसी लगाई गई,वहां फंदे की ऊंचाई,रस्सी या अन्य सामग्री, कमरे की स्थिति,पलंग की स्थिति तथा अन्य भौतिक साक्ष्य क्या थे।

सरकारी अनुदान की करीब चार लाख रुपये की राशि भी जांच के दायरे में...

मृतका के भाई वीरेंद्र जायसवाल ने आर्थिक विवाद का भी आरोप लगाया है उनका कहना है कि उनके पिता के निधन के बाद वर्ष 2025 में शासन की ओर से परिवार को करीब चार लाख रुपये का अनुदान मिला था, आरोप है कि इसी राशि को लेकर नीरज जायसवाल द्वारा कथित रूप से पैसों की मांग की गई, परिजनों के अनुसार अप्रैल में करीब एक लाख रुपये दिए भी गए थे,लेकिन इसके बावजूद निशा को कथित प्रताड़ना से राहत नहीं मिली, यदि यह आर्थिक लेन-देन मामले की जांच का हिस्सा बनता है तो पुलिस के लिए संबंधित बैंक खाते, लेन-देन के रिकॉर्ड, परिजनों के बयान और उपलब्ध दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं,हालांकि अनुदान की राशि और उससे जुड़े कथित विवाद की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

मृतक के परिजन

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की...

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तथा फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची,टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए,मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है,ऐसे मामलों में घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्य बेहद महत्वपूर्ण होते हैं,फंदे की सामग्री,गले के निशान,कमरे की स्थिति,शव की स्थिति,मौके पर मिली बेल्ट अथवा अन्य वस्तुओं तथा शरीर पर मौजूद चोट के निशान का वैज्ञानिक परीक्षण जांच की दिशा तय कर सकता है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुल सकते हैं कई सवालों के जवाब

मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक होगी। रिपोर्ट से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि मौत का चिकित्सकीय कारण क्या था और शरीर पर पाए गए निशानों की प्रकृति क्या है,यदि चिकित्सकीय रिपोर्ट में ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो सामान्य फांसी से अलग परिस्थितियों की ओर संकेत करते हैं तो पुलिस की जांच का दायरा बढ़ सकता है,वहीं यदि रिपोर्ट आत्महत्या के अनुरूप पाई जाती है,तब भी मायके पक्ष द्वारा लगाए गए प्रताड़ना और आर्थिक दबाव के आरोपों की अलग से जांच आवश्यक हो सकती है,इसलिए केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही पूरे मामले का अंतिम आधार मानने के बजाय पुलिस को उपलब्ध सभी परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्यों को जोड़कर निष्कर्ष तक पहुंचना होगा।

मायके पक्ष के आरोपों की भी होनी चाहिए निष्पक्ष जांच

मृतका के परिजनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे निशा की मौत को आत्महत्या नहीं मानते और उन्हें हत्या की आशंका है,उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है,मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच में दोनों पक्षों के बयान दर्ज करना,मृतिका के मोबाइल फोन और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की जांच, घटना से पहले की बातचीत,आर्थिक लेन-देन, पड़ोसियों एवं अन्य संभावित गवाहों के बयान तथा घटनास्थल की परिस्थितियों का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।

आत्महत्या,दुर्घटना या हत्या

जांच के बाद ही सामने आएगी सच्चाई- फिलहाल इस मामले में दो अलग-अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं,ससुराल पक्ष की ओर से घटना को आत्महत्या के रूप में देखा जा सकता है, जबकि मायके पक्ष ने इसे हत्या की आशंका से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं,इन दोनों दावों के बीच वास्तविक सच्चाई पुलिस जांच से सामने आनी है,सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि निशा की मौत वास्तव में किन परिस्थितियों में हुई? क्या उसने स्वयं फांसी लगाई थी? क्या शव को फंदे से उतारने के बाद पलंग पर रखा गया? शरीर पर बताए जा रहे निशान कैसे आए? घटना से पहले घर में कोई विवाद या मारपीट हुई थी? और क्या पैसों को लेकर वास्तव में कोई दबाव बनाया जा रहा था? इन सवालों के जवाब केवल आरोप-प्रत्यारोप से नहीं,बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य, घटनास्थल की वैज्ञानिक जांच और पुलिस विवेचना से सामने आएंगे।

जमीन विवाद में प्राणघातक हमला करने वाले तीन और आरोपी गिरफ्तार

पूर्व में एक आरोपी की हो चुकी है गिरफ्तारी...अम्बिकापुर,दंतेवाड़ा और भोपाल में छिपकर रह रहे थे आरोपी...घटना में प्रयुक्त डंडे बरामद

-संवाददाता-

सूरजपुर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। जमीन विवाद को लेकर परिवार पर लाठी-डंडे से हमला कर प्राणघातक चोट पहुंचाने के मामले में चौकी बसदेई पुलिस ने फरार चल रहे तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है,मामले में पुलिस पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी,पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में एक महिला रिश्तेदार की मदद से अलग-अलग स्थानों पर छिपकर रहने की बात बताई है,आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडे भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार ग्राम जूर निवासी हसीना बीबी ने चौकी बसदेई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहम्मद आयुब के परिवार के साथ उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, इसी विवाद के चलते 14 अप्रैल 2026 को शाम करीब 5 बजे वह अपने ससुर सफी अहमद और बहू सहेबा के साथ खेत में बनाए गए झाला में खाट पर बैठी थी, आरोप है कि इसी दौरान अयुब अंसारी, उसके दोनों लड़के,भतीजा और पत्नी डंडा-लाठी लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और विवाद शुरू कर दिया।

बीच-बचाव करने पहुंचे पति पर किया हमला

रिपोर्ट के मुताबिक,विवाद की आवाज सुनकर हसीना बीबी के पति मो. यासीन मौके पर पहुंचे और झगड़ा शांत कराने का प्रयास किया। आरोप है कि इसी दौरान आयुब अंसारी,उसकी पत्नी, उसके लड़के और भतीजे असलम अंसारी ने कथित रूप से मो. यासीन के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और डंडे से मारपीट कर दी,हमले में मो. यासीन के सिर में गंभीर चोट लगने की बात पुलिस रिपोर्ट में सामने आई है, उन्हें उपचार के लिए तत्काल जिला अस्पताल सूरजपुर ले जाया गया। बीच-बचाव के दौरान बहू,भांजे और ससुर के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है,मामले में हसीना बीबी की रिपोर्ट पर चौकी बसदेई में अपराध क्रमांक 244/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी),351(3), 115(2), 191(1),191(2),109 एवं 249 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

5 अगस्त को असलम अंसारी गिरफ्तार

विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले में पूर्व में फरार चल रहे आरोपी असलम अंसारी को 5 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया था,इसके बाद अन्य आरोपियों की तलाश जारी थी,मामले की गंभीरता को देखते हुए सूरजपुर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने फरार आरोपियों की पतासाजी कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे।

सूचना के आधार पर तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में-पुलिस को फरार आरोपियों के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इसके आधार पर चौकी बसदेई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद आयुब अंसारी पिता स्व. अवैश करनी,उम्र 50 वर्ष,अख्तर रजा पिता मोहम्मद अयुब अंसारी,उम्र 27 वर्ष तथा उमर रजा पिता मो. अयुब अंसारी,उम्र 23 वर्ष, सभी निवासी ग्राम जूर, चौकी बसदेई को पकड़ लिया,पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे एक महिला रिश्तेदार की मदद से पुलिस से बचने के लिए अम्बिकापुर,दंतेवाड़ा और भोपाल में अलग-अलग स्थानों पर छिपकर रह रहे थे।

घटना में प्रयुक्त डंडे बरामद

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कथित रूप से घटना में इस्तेमाल किए गए डंडे बरामद किए। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की गई,पुलिस के अनुसार मामले में अभी एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है, पुलिस फरार आरोपी के संभावित ठिकानों पर पतासाजी कर रही है।

जमीन विवाद से शुरू हुआ था विवाद- पूरे मामले की पृष्ठभूमि में जमीन विवाद बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था, इसी विवाद के दौरान 14 अप्रैल को खेत में मारपीट की घटना हुई,जिसमें एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट आने का आरोप है, पुलिस अब मामले में गिरफ्तार आरोपियों से घटना के संबंध में आगे पूछताछ कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी बसदेई योगेंद्र जायसवाल एवं उनकी टीम की सक्रिय भूमिका रही।

CMYK

100 रूपए महीना मकान कर को लेकर गरमाई सियासत

गुलाब कमरो ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

पूर्व विधायक बोले...महंगाई और बढ़े बिजली बिल के बीच ग्रामीणों पर एक और आर्थिक बोझ क्यों पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की चेतावनी को लेकर भी उठाए सवाल

-रवि सिंह-

एमसीबी,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिले की ग्राम पंचायतों में भवन/मकान कर की प्रस्तावित वसूली को लेकर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है,जिला पंचायत के निर्देशों के अनुसार जिले की तीनों जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में भवन/मकान कर की वसूली किए जाने की बात सामने आने के बाद पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 वार्षिक यानी 100 प्रतिमाह भवन/मकान कर की वसूली की बात सामने आई है,इसी मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने सवाल उठाया है कि जब ग्रामीण जनता पहले से महंगाई, बिजली बिल और रोजगार से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रही है,तब उसके ऊपर अतिरिक्त कर का बोझ क्यों डाला जा रहा है, हालांकि,कर की वास्तविक दर,लागू होने का दायरा,किन भवनों पर यह कर देय होगा और किस-किस श्रेणी को इससे छूट मिलेगी, इन बिंदुओं पर संबंधित पंचायत एवं प्रशासनिक स्तर से स्पष्ट जानकारी सामने आना अभी बाकी है। इसलिए राजनीतिक आरोपों के साथ-साथ इस कर की वैधानिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाना भी महत्वपूर्ण हो गया है।

डबल इंजन सरकार ग्रामीणों की जेब पर भी डालेगी अतिरिक्त बोझ-पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्रामीण जनता पहले ही महंगाई और बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान है, ऐसे समय में मकान कर के रूप में नया आर्थिक बोझ डालने की तैयारी की जा रही है,उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या डबल इंजन सरकार अब महंगाई और बढ़े हुए बिजली बिल के बाद ग्रामीणों से संपत्ति कर वसूलकर उनकी जेब पर एक और हमला करने जा रही है? कमरो का कहना है कि गांवों में रहने वाला गरीब,किसान,मजदूर और राशन कार्डधारी परिवार सीमित आय में अपने दैनिक खर्च पूरे करता है,ऐसे परिवारों पर अतिरिक्त कर लगाया जाता है तो उनके घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ सकता है।

महंगाई के बीच नए कर को लेकर विरोध

पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियां जनहित के बजाय जनविरोधी साबित हो रही हैं,उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार पहले से ही बढ़ती महंगाई और बिजली खर्च से प्रभावित हैं,उनका कहना है कि सरकार को ग्रामीण परिवारों पर नया आर्थिक भार डालने के बजाय उन्हें राहत देने की दिशा में कदम उठाना चाहिए,खासकर गरीब और निम्न आय वाले परिवारों के लिए किसी भी नए कर की व्यवस्था लागू करने से पहले उसके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए।

पंचायत सचिवों पर दबाव का भी आरोप

भवन/मकान कर की वसूली को लेकर ग्राम पंचायत सचिवों पर कथित रूप से बनाए जा रहे दबाव को लेकर भी गुलाब कमरो ने सवाल उठाया है,उन्होंने कहा कि यदि कर वसूली निर्धारित स्तर तक नहीं होने पर सचिवों का वेतन रोकने अथवा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है,तो इससे पंचायत स्तर पर कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव बनेगा,कमरो ने सरकार से सवाल किया कि यदि कर वसूली अनिवार्य है तो सबसे पहले ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों को इसके संबंध में स्पष्ट नियम एवं प्रक्रिया की जानकारी क्यों नहीं दी जाती।

किस कानूनी प्रावधान के तहत लगेगा 1200 सालाना कर-पूर्व विधायक ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल कर की वैधानिकता और उसके दायरे को लेकर उठाया है, उनका कहना है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 1200 वार्षिक भवन/मकान कर किस कानूनी प्रावधान के तहत वसूला जाएगा, इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किन भवनों पर यह कर लागू होगा? क्या सभी ग्रामीण परिवारों से समान दर से वसूली होगी? गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कोई छूट होगी या नहीं? कच्चे और पक्के मकानों के लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी या नहीं? कर निर्धारण का आधार क्या होगा? पंचायतों को प्राप्त राशि का उपयोग किन कार्यों में किया जाएगा? वसूली की प्रक्रिया और शिकायत निवारण की व्यवस्था क्या होगी? इन सवालों पर स्पष्ट जानकारी मिलने के बाद ही ग्रामीणों को कर व्यवस्था की वास्तविक स्थिति समझ में आ सकेगी।

पंचायतों की आय बढ़ाने और ग्रामीणों पर बोझ के बीच संतुलन जरूरी

ग्राम पंचायतों के लिए स्थानीय स्तर पर राजस्व प्राप्त करना विकास कार्यों और स्थानीय प्रशासन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है,लेकिन राजनीतिक विवाद इस बात को लेकर है कि राजस्व जुटाने की व्यवस्था का आर्थिक भार ग्रामीण परिवारों पर कितना पड़ेगा, ऐसे में सरकार और पंचायत प्रशासन के सामने चुनौती यह होगी कि स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने के साथ-साथ गरीब एवं कमजोर परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव न पड़े,यदि मकान कर लागू किया जाना है तो उसकी दर,नियम,छूट,वसूली प्रक्रिया और प्राप्त राशि के उपयोग की जानकारी सार्वजनिक किए जाने से विवाद को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

महंगाई की मार...ऊपर से नया कर: कमरो

गुलाब कमरो ने सरकार से मांग की कि ग्रामीण जनता पर प्रस्तावित अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर पुनर्विचार किया जाए,उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कर वसूली शुरू करने से पहले ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को इसकी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए,उन्होंने कहा कि 'महंगाई की मार,ऊपर से नया कर—ग्रामीण जनता पर आर्थिक प्रहार बंद करो,अब इस मुद्दे पर प्रशासन की ओर से कर की वास्तविक व्यवस्था,कानूनी आधार,लागू होने की तिथि,दर,छूट तथा पंचायतों को मिलने वाले राजस्व के उपयोग को लेकर क्या स्पष्टीकरण आता है,इस पर ग्रामीणों के साथ-साथ राजनीतिक दलों की भी नजर बनी हुई है।

बैकुंठपुर नगर पालिका के 4 विकास कार्यों पर उपाध्यक्ष ने उठाए सवाल, स्वीकृत राशि के पुनः उपयोग की मांग

300.64 लाख के 13 कार्यों में चार को लेकर आपत्ति, एनएच-43 चौड़ीकरण और बाजार विकास का हवाला देकर प्राथमिकता बदलने का अनुरोध

-संवाददाता-

बैकुण्ठपुर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर में अधोसंरचना मद से स्वीकृत विकास कार्यों को लेकर अब नगर पालिका उपाध्यक्ष आशीष यादव ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र सौंपकर स्वीकृत 13 विकास कार्यों की सूची में से चार कार्यों को लेकर पुनर्विचार करने तथा आवश्यकता

नुसार स्वीकृत राशि का उपयोग अधिक जनहितकारी कार्यों में किए जाने का आग्रह किया है। उपाध्यक्ष का पत्र 7 अगस्त 2026 का है। पत्र में बताया गया है कि नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर में अधोसंरचना मद से विभिन्न 13 विकास कार्यों के लिए कुल 300.64 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है,उपाध्यक्ष ने स्वीकृत कार्यों का अवलोकन करने के बाद कुछ कार्यों को वर्तमान परिस्थितियों में दोबारा विचार योग्य बताया है,उनका तर्क है कि यदि ऐसे कार्यों पर राशि खर्च की गई और बाद में परिस्थितियां बदलने के कारण उन्हें दोबारा करना पड़ा,तो सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग नहीं हो सकेगा।

एनएच-43 से एसईसीएल कार्यालय तक पाथवे पर सवाल-कार्य क्रमांक 03 के तहत एनएच-43 से एसईसीएल ऑफिस तक पाथवे निर्माण के लिए 13.66 लाख स्वीकृत किए गए हैं,पत्र में कहा गया है कि एनएच-43 मार्ग का सड़क चौड़ीकरण प्रस्तावित है तथा आगामी चार से छह माह में चौड़ीकरण के लिए बजट जारी होने की संभावना है,ऐसे में वर्तमान में पाथवे निर्माण पर राशि खर्च करने को संभावित रूप से दोहरा व्यय बताया गया है।

प्रमीला होंडा से नगर पालिका तक सड़क भी पुनर्विचार के दायरे में-कार्य क्रमांक 04 में मुख्य मार्ग पर प्रमीला होंडा से नगर पालिका परिसर तक बीटी सड़क निर्माण के लिए 36.79 लाख स्वीकृत किए गए हैं। उपाध्यक्ष ने आशंका जताई है कि भविष्य में इस मार्ग के चौड़ीकरण की स्थिति में वर्तमान निर्माण पर खर्च की गई राशि का अपेक्षित उपयोग नहीं हो पाएगा।

इंदिरा पार्क से जनपद तितरा सड़क पर भी सवाल- कार्य क्रमांक 09 में इंदिरा पार्क के सामने से जनपद तितरा तक बीटी रोड मरम्मत के लिए 48.54 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

स्मार्ट मीटर के विरोध से लेकर नगर पालिका चुनाव की तैयारी तक,कांग्रेस ने बनाई रणनीति

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैकुंठपुर की द्वितीय मासिक बैठक में संगठन को वार्ड और बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर,घर-घर पहुंचकर जनता की आपत्तियां जुटाने का निर्णय...

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैकुंठपुर की द्वितीय मासिक बैठक शनिवार को आयोजित की गई,बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों के साथ आगामी नगर पालिका चुनाव की तैयारियों तथा आम जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने तथा बिजली बिलों में वृद्धि को प्रमुख जनमुद्दा बताते हुए इसके विरोध में जनजागरूकता अभियान को तेज करने का निर्णय लिया।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता केवल संगठनात्मक बैठकों तक सीमित न रहें,बल्कि लगातार वार्डों और मोहल्लों में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझें और उन्हें शासन-प्रशासन के समक्ष उठाएं। आगामी नगर पालिका चुनाव को देखते हुए संगठन को बूथ एवं वार्ड स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई।

स्मार्ट मीटर के विरोध में घर-घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता

बैठक का प्रमुख मुद्दा स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिल रहे,कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों में वृद्धि को लेकर आम लोगों में असंतोष है। इसे लेकर पार्टी ने जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है,बैठक में बताया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लोगों से स्मार्ट मीटर के विरोध में फॉर्म भरवाने का अभियान शुरू किया है। इसके माध्यम से आम नागरिकों की आपत्तियों एवं समस्याओं को एकत्रित कर संगठित रूप से शासन-प्रशासन के समक्ष रखने की तैयारी है, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से जुड़े लोगों के सवालों को स्थानीय स्तर पर उठाने के साथ व्यापक स्तर पर भी आवाज बुलंद की जाएगी।

नगर पालिका चुनाव को लेकर वार्डों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश-बैठक में आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपने-अपने वार्डों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए,कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे नियमित रूप से जनता के बीच पहुंचें,स्थानीय समस्याओं और परेशानियों को समझें तथा संबंधित अधिकारियों के समक्ष उन्हें उठाकर समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करें,बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि चुनाव की तैयारी केवल चुनाव के समय शुरू करने के बजाय अभी से वार्ड स्तर पर संगठन को सक्रिय किया जाए,प्रत्येक वार्ड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने तथा जनता के साथ लगातार संवाद बनाए रखने पर जोर दिया गया।

बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर-कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आगामी नगर पालिका चुनाव को देखते हुए संगठन को बूथ और वार्ड स्तर तक मजबूत करना आवश्यक है, इसके लिए कार्य कर्ताओं को लगातार जनता के संपर्क में रहने, स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने और जनहित से जुड़े मामलों में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही गई, बैठक में यह भी कहा गया कि संगठन की मजबूती केवल पदाधिकारियों की संख्या से नहीं,बल्कि कार्यकर्ताओं की जमीनी सक्रियता से तय होती है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में नियमित रूप से जनता के बीच पहुंचकर संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभानी होगी।

जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन जारी रखने का निर्णय-ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने स्मार्ट मीटर, बिजली बिलों में वृद्धि तथा अन्य जनसमस्याओं को लेकर आगे भी जनजागरूकता और जनआंदोलन जारी रखने की बात कही,पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि जनता से जुड़े मुद्दों को चिन्हित कर उन्हें संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाए और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलनात्मक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं,बैठक में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आगामी नगर पालिका चुनाव में जनता के बीच पार्टी की सक्रियता और जनसमस्याओं को लेकर संघर्ष प्रमुख आधार रहेगा।

बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद

बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, नगर पालिका बैकुंठपुर चुनाव प्रभारी वेदांती तिवारी,ब्लॉक अध्यक्ष आशीष यादव,अजय सिंह, सुरेंद्र तिवारी,बृजवासी तिवारी,अनिल जायसवाल, प्रवीण भट्टाचार्य,पार्षद राहुल गुप्ता,अंकित गुप्ता,लालदास सहित महिला कांग्रेस की रकीबा बेगम,ममता गुप्ता,अर्चना एवं पूजा मांझी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, बैठक के माध्यम से कांग्रेस ने एक ओर स्मार्ट मीटर और बिजली बिल के मुद्दे को लेकर जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया,वहीं दूसरी ओर आगामी नगर पालिका चुनाव के लिए वार्ड एवं बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की रणनीति तैयार की।

तिरंगा यात्रा और कलश वंदन अभियान को लेकर भाजपा की जिला स्तरीय बैठक संपन्न

8 से 14 अगस्त तक मंडल एवं बूथ स्तर पर निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा,14 अगस्त को जिला मुख्यालय में मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

-संवाददाता-

बैकुण्ठपुर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय छिंदडांड़, बैकुण्ठपुर में तिरंगा यात्रा,कलश वंदन यात्रा एवं समरसता संकल्प अभियान को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करते हुए मंडल एवं बूथ स्तर तक कार्यक्रमों को व्यापक रूप से आयोजित करने और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर देशव्यापी तिरंगा यात्रा के तहत मंडल एवं बूथ स्तर पर प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा लगाने के अभियान को सफल बनाया जाएगा, उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं के योगदान का स्मरण किया जाएगा, उन्होंने कहा कि देश के निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को जोड़ना जरूरी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

8 से 14 अगस्त तक मंडलों में तिरंगा यात्रा-जिला महामंत्री पंकज गुप्ता ने बैठक में कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के प्रत्येक मंडल में 8 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न स्थानों से मंडल स्तर पर यात्राएं निकाली जाएंगी और पार्टी कार्यकर्ता इसमें सक्रिय सहभागिता निभाएंगे,उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा,साथ ही कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक अभियान को पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस-बैठक में निर्णय लिया गया कि 14 अगस्त को जिला मुख्यालय में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा,इस अवसर पर देश के विभाजन के दौरान प्रभावित हुए लोगों को स्मरण करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

गुरु रविदास जयंती वर्ष में समरसता संकल्प अभियान-प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णबिहारी जायसवाल ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर गुरु पूर्णिमा से 20 फरवरी 2027 तक भव्य समरसता संकल्प अभियान एवं कलश वंदन यात्रा आयोजित की जा रही है,उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य संत गुरु रविदास जी के जीवन, समानता और सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से तिरंगा यात्रा सहित सभी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया,बैठक में कार्यक्रमों को मंडल, बूथ एवं स्थानीय स्तर पर प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा पार्टी कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया,इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष बसंत राय,अशोक जायसवाल,राजेश सिंह, रविशंकर राजवाड़े, अनिल साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा,अल्पसंख्यक मोर्चा संभाग प्रभारी समाउदीन सिद्धिकी,नगर पालिका अध्यक्ष अरुण जायसवाल,नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री सिंह,जिला मंत्री ईश्वर राजवाड़े,जिला मीडिया प्रभारी तीरथ राजवाड़े सहित पार्टी के विभिन्न मोर्चों, प्रकोष्ठों एवं मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे,बैठक में महिला मोर्चा, भाजयुमो,किसान मोर्चा,अनुसूचित जाति एवं जनजाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा और अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। पार्टी ने आगामी दिनों में तिरंगा यात्रा और समरसता अभियान को व्यापक जन सहभागिता के साथ आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है।

चाकू और पिस्टलनुमा हथियार लेकर घूम रहे दो युवक ग्रामीणों के सहयोग से पकड़े गए

डायल 112 के आरक्षक की सूझबूझ से समय रहते हुई कार्रवाई,पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने नगद पुरस्कार देने की घोषणा की

-संवाददाता-

सूरजपुर,08 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

डायल 112 में तैनात आरक्षक की सजगता, सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से रामानुजनगर थाना क्षेत्र में चाकू एवं पिस्टलनुमा हथियार लेकर घूम रहे दो संदिग्ध युवकों को ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ लिया गया,आरक्षक द्वारा समय रहते दी गई सूचना के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से धारदार चाकू तथा पिस्टल जैसा दिखाई देने वाला हथियार बरामद किया। मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है, आरक्षक की कर्तव्यनिष्ठा और सतर्कता की पुलिस विभाग में सराहना की गई है,पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल ने आरक्षक के इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

ग्रामीणों के सहयोग से मौके पर ही रोके गए संदिग्ध-पुलिस के अनुसार 6 अगस्त 2026 की शाम थाना रामानुजनगर पुलिस को थाना सूरजपुर के डायल 112 में तैनात आरक्षक प्रदीप सोनवानी ने सूचना दी कि ग्राम मंहगई हरिजनपारा में एक बलेनो कार क्रमांक सीजी 29 एजी 1126 में दो व्यक्ति सवार हैं। आरक्षक को सूचना मिली थी कि कार में सवार चालक और उसका साथी पिस्टल एवं चाकू लेकर घूम रहे हैं, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आरक्षक प्रदीप सोनवानी ने ग्रामीणों के सहयोग से दोनों संदिग्धों को मौके पर ही रोक लिया,इस दौरान उन्होंने तत्काल रामानुजनगर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी,जिसके बाद पुलिस टीम बिना देरी किए मौके पर पहुंची।

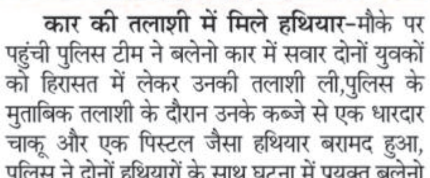

कार की तलाशी में मिले हथियार-मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बलेनो कार में सवार दोनों युवकों को हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली,पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक धारदार चाकू और एक पिस्टल जैसा हथियार बरामद हुआ, पुलिस ने दोनों हथियारों के साथ घटना में प्रयुक्त बलेनो कार को भी जप्त कर लिया,बरामद पिस्टलनुमा हथियार की वास्तविक प्रकृति और उसकी वैधानिक स्थिति जांच का विषय है।

दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज-पुलिस ने आरोपियों की पहचान कैफ अंसारी पिता सहाबुद्दीन अंसारी, उम्र 24 वर्ष तथा विकास रवि पिता स्व.रामकुमार रवि, उम्र 19 वर्ष, दोनों निवासी नावापारा खुर्द के रूप में की है,मामले में थाना रामानुजनगर में अपराध क्रमांक 237/26 दर्ज किया गया है, पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं धारा 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है,दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

समय पर सूचना से टली संभावित घटना-पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में डायल 112 के आरक्षक प्रदीप सोनवानी की सतर्कता महत्वपूर्ण रही, हथियार लेकर संदिग्ध रूप से घूम रहे युवकों के संबंध में समय रहते सूचना मिलने और ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें मौके पर रोक लिए जाने के कारण पुलिस को तत्काल कार्रवाई का अवसर मिला।

मिलिंद गाबा और प्रिया बेनीवाल के रिश्ते में अनबन की चर्चा

सिंगर और 'बिग बॉस ओटीटी' सीजन 1 के कंटेस्टेंट मिलिंद गाबा और उनकी पत्नी प्रिया बेनीवाल इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते में अनबन की अफवाहें तेज हो गई हैं। इसकी वजह दोनों का इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो करना बताया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने जैसे ही इस बदलाव पर ध्यान दिया, उनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। मिलिंद गाबा और प्रिया बेनीवाल की शादी को चार साल से ज्यादा समय हो चुका है। दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के साथ नजर आते रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी जिंदगी से जुड़े कई पल साझा करते रहे हैं। ऐसे में अचानक एक-दूसरे को अनफॉलो करने की खबर ने उनके प्रशंसकों का ध्यान खींचा है। हालांकि, अभी तक मिलिंद गाबा या प्रिया बेनीवाल की ओर से रिश्ते में किसी तरह की अनबन,अलगाव या वैवाहिक विवाद की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को फिलहाल सिर्फ अफवाह के तौर पर ही देखा जा रहा है। इंस्टाग्राम पर अनफॉलो से शुरू हुई चर्चा सेलेब्रिटी कपल्स के सोशल मीडिया व्यवहार पर प्रशंसकों की नजर बनी रहती है। मिलिंद और प्रिया के मामले में भी ऐसा ही हुआ। दोनों के एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो न करने की बात सामने आने के बाद फैंस ने इस बदलाव को नोटिस किया।

रणवीर सिंह की धुरंधर ने फिर किया धमाल

बनी नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली दुनिया की नॉन-इंग्लिश फिल्म आदित्य धर की धुरंधर भले ही सिनेमाघरों से उतर गई है,लेकिन ओटीटी पर अब भी इसका जादू छाया हुआ है। इस फ्रैंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े. फिल्म की पॉपुलैरिटी सिर्फ सिनेमाघरों तक ही सीमित नहीं रही.नेटफ्लिक्स पर आने के बाद भी इसे दुनिया भर में बहुत से दर्शकों ने देखा। शायद यही वजह है कि धुरंधर अब दुनिया भर में नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी भारतीय नॉन-इंग्लिश फिल्म बनकर उभरी है । नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सारंडोस ने हाल ही में इस फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया कि यह उन भारतीय फिल्मों में से एक थी जिन्होंने स्ट्रीमिंग सर्विस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे यह साबित हुआ कि इसकी लोकप्रियता सिनेमाघरों से कहीं ज्यादा थी।

टेड सारंडोस से पूछा गया कि क्या भारतीय फिल्मों और शो का भी दुनिया भर में वैसा ही असर पड़ रहा है,जैसा कोरियाई शो स्क्विड गेम का पड़ा था। तब उन्होंने बताया कि आदित्य धर की धुरंधर इस साल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-इंग्लिश फिल्म थी। उन्होंने कहा, धुरंधर इस साल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-इंग्लिश फिल्म थी. यह हर दूसरी इंग्लिश फिल्म से ज्यादा देखी गई और इसे देखने के मामले में यह सिर्फ यूएस और यूके से पीछे रही। बातचीत के दौरान,सारंडोस ने बताया कि लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि भारत में साउथ कोरिया के स्क्विड गेम या स्पेन के ला कासा डे पैपेल (मनी हाइस्ट) जैसा ग्लोबल कल्चरल फेनोमेनन कब देखने को मिलेगा। उन्होंने जवाब में कहा कि भारत पहले से ही लगातार ग्लोबल लेवल पर सफल कंटेंट बना रहा है और ऐसे पल ऑल द टाइम आते रहते हैं.

टेड सारंडोस ने कहा, इसके सिनेमा के जरिए आने की संभावना ज्यादा है। जब हमने सेक्रेड गेम्स बनाई थी, तब टेलीविजन का स्वरूप बिल्कुल अलग था। इसलिए,अब तक के इतिहास और आगे जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि यह सिनेमा के रूप में ही सामने आएगा.

उन्होंने आगे कहा...2024 से हर हफ्ते ग्लोबल टॉप 10 में कोई न कोई भारतीय फिल्म या सीरीज़ रही है और यह उस एल्गोरिदम का नतीजा है जो आपको चीजे खोजने में मदद करता है. यह बात ऐसी है जो मुझे बहुत पसंद है। इसी वजह से, इस साल दुनिया भर में नेटफ्लिक्स पर भारतीय कंटेंट को 3.5 अरब घंटे देखा गया है।

आदित्य धर की फ्रैंचाइजी में रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल,संजय दत्त, आर.माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे अहम किरदार में नजर आए थे. इस फिल्म को आदित्य धर, ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले मिलकर प्रोड्यूस किया है। यह स्पाई-एक्शन फिल्म पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी. इस साल मार्च में इसका दूसरा भाग धुरंधर- द रिवेंज सिनेमाघरों में आया और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई।

अमीषा पटेल बोलीं...कभी नहीं करूंगी शादी, एक मर्द को संभालना मेरे बस की बात नहीं

अभिनेत्री अमीषा पटेल ने हाल ही में एक्स पर अपने आस्कएमी सेशन के दौरान शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया। जब एक फैन ने उनसे शादी की योजना के बारे में पूछा तो अमीषा ने दोटूक जवाब देते हुए कहा कि वो कभी शादी नहीं करेंगी। 49 वर्षीय अभिनेत्री ने बताया कि वो सिंगल रहकर बेहद खुश हैं और उनके पास 100 से अधिक करीबी दोस्त और परिवार हैं जो उनसे प्यार करते हैं।

एक्स पर एक फैन ने उनसे पूछा...आप शादी कब कर रही हैं? अमीषा का जवाब सीधा और साफ था। उन्होंने लिखा,कभी नहीं। में अकेले रहकर बेहद खुश हूं। मेरे पास प्यार करने वाले 100 करीबी दोस्त और परिवार हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई एक आदमी आकर ये सब कुछ बदल दे। ये जोखिम मैं नहीं उठा सकती। अमीषा ने अब पूरी तरह साफ कर दिया है कि वो कभी शादी के बंधन में नहीं बंधने वाली हैं।

रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में अमीषा ने बताया था कि उन्होंने अपना एक गंभीर रिश्ता इसलिए तोड़ दिया था,क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड नहीं चाहता था कि वो फिल्मों में काम करें। अमीषा ने कहा...जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं,वे आपके करियर को आगे बढ़ने देंगे। मैंने अपने करियर के लिए बहुत कुछ खोया है और प्यार के लिए भी बहुत कुछ कुर्बान किया है। मैंने दोनों के लिए फैसले लिए हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। हालांकि, तब अमीषा ने बताया था कि उन्होंने शादी के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। उन्होंने कहा था,अगर मुझे कोई सही इंसान मिलता है तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। मुझे आज भी कई बड़े परिवारों से रिश्ते आते हैं और मेरी उम्र से आधे लड़के भी डेट पर ले जाना चाहते हैं। मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि इंसान का मानसिक रूप से परिपक्व होना जरूरी है। मुझसे बड़े कई लोगों का दिमाग मक्खी जैसा होता है।

बता दें कि अमीषा का सबसे चर्चित रिश्ता निर्देशक विक्रम भट्ट के साथ रहा। शादीशुदा विक्रम के साथ 5 साल लिव-इन में रहने के कारण उनका घरवालों से भी विवाद हुआ, हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए।अगर काम की बात करें तो 5 साल के लंबे ब्रेक के बाद अमीषा ने साल 2023 में सनी देओल के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 से पर्दे पर धमाकेदार वापसी की थी।

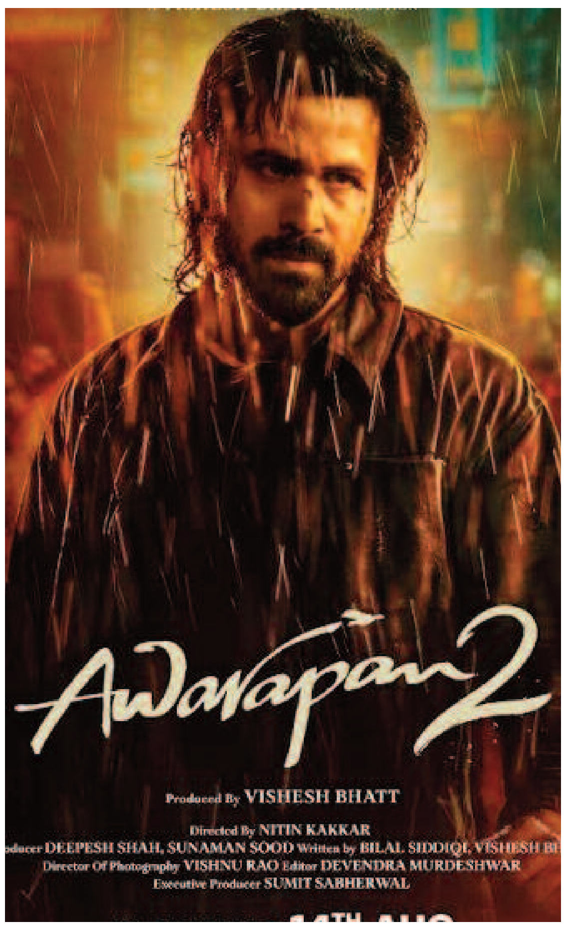

आवारापन 2 पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची,9 बदलाव के बाद मिली ये रेटिंग

इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 अपनी रिलीज के काफी करीब है। विशेष भट्ट द्वारा निर्मित और नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित,ये एक एक्शन थ्रिलर है जिसका इसी नाम से पहला भाग 2007 में आया था। सीक्वल में इमरान के साथ दिशा पाटनी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। ताजा अपडेट है कि निर्माताओं ने फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास सौंपा था,जहां से इसे प्रमाण-पत्र मिल गया है। हालांकि फिल्म में काफी बदलाव किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जांच समिति ने फिल्म निर्माताओं को इसमें 9 संशोधन करने के निर्देश दिए हैं।सेंसर बोर्ड ने फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक दृश्यों को कम करने के लिए कहा है। अपशब्दों को कम करने और नशीली दवाओं, धूम्रपान और बाल तस्करी के खिलाफ चेतावनी जोडने् जैसे बदलाव के निर्देश भी दिए गए हैं। इन सभी बदलाव के बाद, 5 अगस्त को बोर्ड ने 9 देकर आवारापन 2 को पास किया।यूए 16+ प्रमाणपत्र के साथ फिल्म को मिली मंजूरी आवारापन 2 की अवधि कुल अवधि 140 मिनट और 20 सेकंड है। मतलब फिल्म 2 घंटे, 20 मिनट, 20 सेकंड तक दर्शकों का मनोरंजन करती रहेगी।चूकि फिल्म को 2 घंटे, 20 मिनट, 20 सेकंड मिला है, इसलिए 16 साल या उससे ऊपर की उम्र वाले दर्शक अपने माता-पिता के मार्गदर्शन में देख सकेंगे।14 अगस्त,2026 को फिल्म हिंदी भाषा में अंग्रेजी सबटाइटल के साथ रिलीज होगी। इसकी टक्कर सनी देओल अभिनीत फिल्म बटवारा 1947 से होगी।

खेल समाचार

फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले लियोनेल मेसी को मिली बम से उड़ाने की धमकी

स्पैनिश,08 अगस्त 2026 ।एक पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में 2026 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान लियोनेल मेसी को कई गंभीर सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में टूर्नामेंट के दौरान कई फुटबॉल स्टार्स, खिलाड़ियों, अधिकारियों और रेफरी को बम की धमकियों,पीछा करने की घटनाओं और धमकी भरे संदेशों का जिक्र किया गया है। सबसे चिंताजनक घटनाओं में से एक घटना डलास में अर्जेंटीना और जॉर्डन के मैच से पहले हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, एक कॉलर ने डलास एयरपोर्ट पर संपर्क किया और दावा किया कि वह और दो अन्य लोग घर पर बने बम और एआर-15 राइफल लेकर स्टेडियम की ओर जा रहे हैं। इस धमकी में दोनों टीमों के पुलिस अधिकारियों और खिलाड़ियों को निशाना बनाया गया था, जिसमें खास तौर पर मेसी का नाम लिया गया था। अटलांटा में अर्जेंटीना और मिस्र के मैच से पहले एक और परेशान करने वाली धमकी सामने आई। एक यूज़र ने कथित तौर पर स्टेडियम में घुसने और अपने शरीर पर बंधे विस्फोटक से मेसी पर हमला करने की धमकी दी। पुलिस को एक अलग कॉल भी मिली जिसमें दावा किया गया कि स्टेडियम के अंदर अलग-अलग कूड़ेदानों में तीन बम रखे गए हैं, जिसके बाद विस्फोटक विशेषज्ञों, डॉग हैंडलर्स और के-9 टीमों ने पूरे वेन्यू की तलाशी ली। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड कप के दौरान सबसे ज़्यादा धमकियां मेसी को ही मिलीं। अमेरिका और हिस्सा लेने वाले देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने एफबीआई के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाया ताकि पूरे टूर्नामेंट के दौरान आतंकवाद से जुड़े अलर्ट, हिंसक धमकियों और संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। अधिकारियों ने खिलाड़ियों, उनके परिवारों और टूर्नामेंट वेन्यू से जुड़ी धमकियों पर भी कड़ी नज़र रखी।

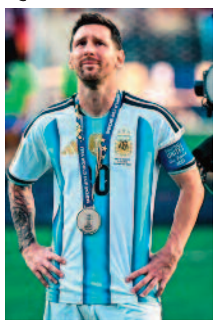

भारत की यू-15 टीम की कमान संभालेंगे रंजीत बजाज

नई दिल्ली,08 अगस्त 2026 । भारतीय फुटबॉल में इस समय रंजीत बजाज का नाम एक बार फिर चर्चा में है। मिनर्वा अकादमी के संस्थापक और प्रमुख के रूप में युवा खिलाड़ियों को तैयार करने वाले बजाज ने एआईएफएफ से भारत की -15 टीम की जिम्मेदारी देने की मांग की है। हालांकि, इसे सीधे तौर पर यह कहना सही नहीं होगा कि उन्होंने एआईएफएफ का कोई औपचारिक ऑफर ठुकरा दिया और अब उसी पद को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उपलब्ध रिपोर्टों में तस्वीर इससे थोड़ी अलग है।

बजाज ने एआईएफ एफ अध्यक्ष कल्याण चौबे से भारत की -15 टीम की कमान सौंपने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर उन्हें काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाए और अपनी टीम व सिस्टम के हिसाब से फैसले लेने का अधिकार मिले,तो वह भारतीय युवा फुटबॉल को नई दिशा दे सकते हैं। उनका जोर सिर्फ किसी एक टूर्नामेंट पर नहीं,बल्कि लंबे समय की खिलाड़ी विकास योजना पर है। बजाज का लक्ष्य 2034 विश्व कप और उसके बाद के बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए मजबूत भारतीय पीढ़ी तैयार करना है।

मिनर्वा की लिवरपूल पर 6-0 की जीत ने बढ़ाई चर्चा

बजाज के दावे को मजबूती उस समय मिली जब मिनर्वा अकादमी की -15 टीम ने स्पेन में Mediterranean International Cup मे´´ Liverpool -15 को 6-0 से हरा दिया। यह भारतीय ग्रासरूट फुटबॉल के लिए बेहद चर्चित नतीजा रहा। इस प्रदर्शन के बाद यूरोप के क्लबों के स्काउट्स ने भी मिनर्वा के खिलाड़ियों में दिलचस्पी दिखाई। बजाज ने बताया था कि स्पेन और इंग्लैंड के शीर्ष डिविजन क्लबों के स्काउट्स ने खिलाड़ियों के सीव्ही और वीडियो फुटेज मांगे।

नीरज चोपड़ा के नक्श-ए-कदम पर चला यह युवा भारतीय जांबाज

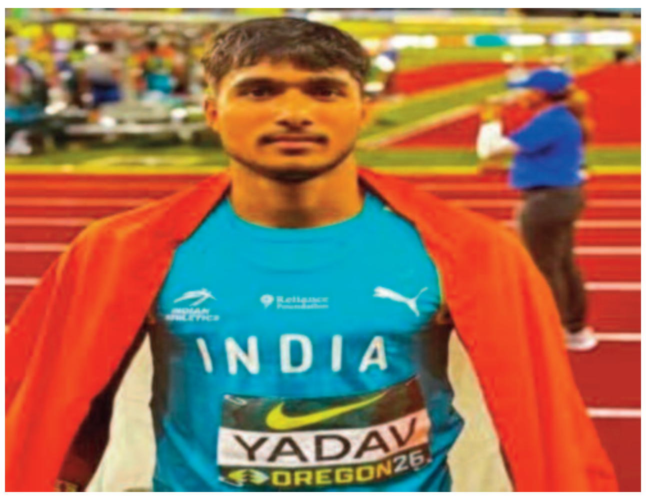

नई दिल्ली,08 अगस्त 2026। वर्ल्ड एथलेटिक्स 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत के युवा और प्रतिभाशाली जैवलिन थ्रोअर आशीष यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का खाता खोल दिया है। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत (सिल्वर) पदक अपने नाम कर लिया है। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ ही आशीष ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर देश का मान बढ़ा दिया है और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

तीसरे राउंड के दमदार थ्रो ने दिलाया ऐतिहासिक पदक

मुकाबले की शुरुआत से ही एथलीटों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। आशीष यादव ने अपने तीसरे ही प्रयास में भाले को 74.09 मीटर की दूरी तक फेंका, जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस बेहतरीन और सधे हुए थ्रो ने उन्हें सीधे पोडियम पर पहुंचा दिया और देश के लिए सिल्वर मेडल पक्का कर दिया। वहीं, इस स्पर्धा में भारत की तरफ से चुनौती पेश कर रहे दूसरे एथलीट टी. धरणिधरन ने भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए 72.35 मीटर के थ्रो के साथ छठा स्थान हासिल किया।

ओलंपिक लीजेंड नीरज चोपड़ा के खास क्लब में हुई एंट्री

इस शानदार उपलब्धि के साथ ही 19 वर्षीय आशीष यादव ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया है। वह दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और देश के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के बाद इस प्रतिष्ठित इवेंट में रजत पदक जीतने वाले देश के केवल दूसरे पुरुष एथलीट बन गए हैं। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने साल 2016 में पोलैंड में आयोजित इसी चैंपियनशिप के दौरान स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और 86.48 मीटर का ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो आज भी अटूट है।

दक्षिण अफ्रीका के एथलीट ने अपने नाम किया गोल्ड

इस रोमांचक और कड़े मुकाबले में स्वर्ण पदक दक्षिण अफ्रीका के जीन-हेंड्रिक हेयमैन के हाथ लगा। उन्होंने अपने छठे और आखिरी यानी निर्णायक प्रयास में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाले को 80.50 मीटर की दूरी तक फेंका। उनके इस थ्रो ने सीजन का 20 वर्ल्ड लीड बनाते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। हालांकि, विदेशी धरती पर भारतीय एथलीटों का यह जुझारू प्रदर्शन यह साबित करता है कि आने वाले समय में देश का एथलेटिक्स भविष्य बेहद उज्जवल है।

कार्यालय सेनानी 12वी (भा./र.) वाहिनी छसबल रामानुजगंज - बलरामपुर (छ0ग0)

क्रमांक-12वीं बटा0/छसबल/रा0गंज/सा0अ0//874/2026, दिनांक-05/08/2026

-:: खुली निविदा (प्रथम) आमंत्रण::-

सेनानी 12 वीं वाहिनी (भा./र.) छसबल रामानुजगंज जिला-बलरामपुर (छ.ग.) में पीसीएण्डसार मद के अंतर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य के लिए सेनानी 12वीं वाहिनी की ओर से सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से 03 लिफाफा में (लिफाफा ''अ'' में टेक्नीकल बीड एवं लिफाफा ''ब'' में फाइनेंशियल बीड) निर्माण कार्य बावत् मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। सील बंद लिफाफा के ऊपर निविदा सूचना क्रमांक तथा निविदाकर्ता का पूरा नाम / पता स्पष्ट लेख किया जाना आवश्यक है।

क्र0	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अमानत राशि
01	वाहिनी मुख्यालय में परेड ग्राउण्ड का लेवलिंग (समतलीकरण कार्य	9.52 लाख	9520/-
02	मिसलिनियस स्टोर निर्माण कार्य	9.46 लाख	9460/-
03	जीओएस मेस/रेस्ट हाऊस का मरम्मत एवं रेनोवेशन कार्य	4.56 लाख	4560/-

01. निविदा आवेदन करने की तिथि 08/08/2026 से 12/08/2026 के 10.30 बजे से शाम 05.00 बजे तक ।
02. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि - 13/08/2026 से 20/08/2026 के 10.30 बजे से शाम 05.00 बजे तक
03. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि - 27/08/2026 के अपरान्ह 03.00 बजे तक ।
04. निविदा खोलने की तिथि - 29/08/2026 के पूर्वाहन 11.00 बजे, निविदाकारों की उपस्थिति में खोला जावेगा ।

नोट- निविदा प्राप्त करने हेतु राशि - 750 / - (सात सौ पच्चास रूपये मात्र) का ई-चालान सेनानी 12वीं (भा./र.) वाहिनी सबल रामानुजगंज जिला-बहरामपुर (छ.ग.) के नाम लेखा शीर्ष 2055 पुलिस,लघु शीर्ष-104 विशेष पुलिस योजना के नाम से स्वीकार होगा। श्रेणी वर्ग डी एवं निविदा की अन्य जानकारी एवं शर्ते कार्यालय से प्राप्त निविदा फार्म में उपलब्ध करा दी जायेगी।

जी.नं.- 262702591/2

सेनानी
12वी (भार) वाहिनी छसबल
रामानुजगंज-बलरामपुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-2,जिला-सरगुजा,छग0

रा.प्र.क्र. /अ-6/2025-2026

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका विनिता पैकरा पति स्व. जुगन साय पैकरा व अन्य जाति कंवर, निवासी ग्राम भफौली, थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा ग्राम हसुंली स्थित भूमि खसरा नंबर 157 /2 कुल रकबा 0.011 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो में वर्तमान मृत खातेदार स्व0 जुगन साय पिता धरमजीत का नाम विलोपित कराते हुए उनके विधिक वारिशों के नाम पर फौती दर्ज कराने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 19/08/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 05/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील)

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-2

सरगुजा बीज उत्पादक प्रक्रिया विपणन एवं बहु. सहकारी समिति मर्यादित सरगंवा पंजीयन क्रमांक 2198

विकासखण्ड - अम्बिकापुर की लिये संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सदस्यता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम

क्रं.	सदस्यता सूची प्रकाशन कार्यक्रम	दिनांक
1	समन्वयक संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सदस्य सूची का प्रदाय	12.08.2026
2	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सदस्य सूची का प्रकाशन एवं सदस्यों को सूचना प्रेषण ।	13.08.2026
3	सदस्यों से आपत्ति प्राप्त करने की अवधि	14.08.2026 20.08.2026
4	आपत्तियों का निराकरण एवं अंतिम सदस्यता का सूचि का प्रकाशन	21.08.2026
5	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी अंतिम सदस्यता सूची पर अपील (अंतिम प्रकाशन के तीन दिन के भीतर) अपीलीय अधिकारी के समक्ष	22.08.2026 से 24.08.2026
6	अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निराकरण आदेश पारित (सात दिवस की समयावधि में)	31.08.2026
7	अपील मान्य किये जाने की स्थिति में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संशोधित सदस्यता सूची (चिन्हित प्रति जारी करना)	01.09.2026

सैनाथ केरकेट्टा
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
सरगुजा बीज उत्पादक प्रक्रिया विपणन एव बहु. सहकारी सोसाइटी मर्या. सरगंवा, पं.क्रं 2198

शिक्षा विभाग ने 700 शिक्षकों के ट्रांसफर किया

400 नाम रोके,कारण नहीं बताए,अगली बार शिक्षक ऑनलाइन भेज सकेंगे ट्रांसफर रिक्वेस्ट

रायपुर,08 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लंबे समय से चल रहे ट्रांसफर के इंतजार को लेकर शिक्षा विभाग ने आखिरकार आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने करीब 700 शिक्षकों का ट्रांसफर किया है। वहीं अलग-अलग कारणों से करीब 400 शिक्षकों के नाम अंतिम सूची से हटा दिए गए। अब विभाग अगले चरण में ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम शुरू करने की तैयारी पर भी मंथन कर रहा है। दरअसल,ट्रांसफर के लिए विभाग ने पहले करीब 1,600 शिक्षकों की लिस्ट तैयार की थी। इसके बाद इस लिस्ट की समीक्षा की गई और संख्या कम करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के बाद करीब 1,000 शिक्षकों की संशोधित लिस्ट तैयार हुई। अंतिम जांच में भी तय नियमों के मुताबिक नहीं पाए गए करीब 400 नाम हटा दिए गए। इसके बाद बची लिस्ट में शामिल करीब 700 शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी किए गए हैं।

आवेदन और सिफारिश के आधार पर बनी थी लिस्ट

जानकारी के मुताबिक,ट्रांसफर के लिए शिक्षकों से मिले आवेदनों और अलग-अलग स्तर से आई सिफारिशों के आधार पर नामों की लिस्ट तैयार की गई थी। इसके बाद विभाग ने हर केस की जांच की। शुरुआती लिस्ट से लेकर अंतिम लिस्ट तक कई स्तर पर जांच हुई। इसी दौरान करीब 400 नाम हटा दिए गए। अब अंतिम लिस्ट में शामिल शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म हो गया है। ट्रांसफर हुए शिक्षकों को अब नए स्कूल में ज्वाइन करना होगा।

इन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया गया

शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर की प्रक्रिया में स्कूलों की पढ़ाई और बच्चों के हित को प्राथमिकता दी। जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पहले ही कम है, वहां से शिक्षक हटाने से बचा गया है। युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों, सिंगल टीचर वाले स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों और ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया गया। जिनके जाने से स्कूल शिक्षक विहीन हो सकता था। इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में ट्रांसफर के मामलों और ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के मामलों को भी अंतिम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। विभाग का कहना है कि किसी शिक्षक के ट्रांसफर से स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ सकता है।

अगली बार ऑनलाइन ट्रांसफर का सिस्टम बनाने की तैयारी

मौजूदा ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग अब आगे की व्यवस्था को ऑनलाइन करने पर भी विचार कर रहा है। विभाग में शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने का सिस्टम शुरू करने को लेकर चर्चा चल रही है। अगर यह सिस्टम लागू होता है तो शिक्षक एक तय पोर्टल पर जाकर खुद ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। इससे ट्रांसफर की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने और आवेदन का समय पर निराकरण करने में मदद मिल सकती है। विभाग दूसरे राज्यों में चल रहे ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम का भी अध्ययन कर रहा है। तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की जांच के बाद सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। फिलहाल करीब 700 शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी हो चुके हैं। अब इन शिक्षकों की नजर नए पदस्थापना वाले स्कूलों पर है।

दुर्ग पुलिस ने 1.20 करोड़ के नशीले पदार्थ किए नष्ट

66 मामलों में जब्त 138 किलो गांजा, हेरोइन, टैबलेट-कैप्सूल और सीरप शामिल

दुर्ग-भिलाई,08 अगस्त 2026। दुर्ग पुलिस ने अलग-अलग 66 मामलों में जब्त किए गए करीब 1.20 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति की निगरानी में की गई। पुलिस के मुताबिक,नष्ट किए गए नशीले पदार्थों में 138.196 किलो गांजा, 114.56 ग्राम हेरोइन, 1,758 नशीली टैबलेट, 2,772 नशीले कैप्सूल और 837 नशीली दवाओं के सीरप शामिल हैं।

नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए भिलाई स्टील प्लांट के एसएमएस-03 प्लांट स्थित भस्मीकरण संयंत्र का इस्तेमाल किया गया। यहां तय प्रक्रिया और सुरक्षा नियमों के तहत गांजा और दूसरे नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। वहीं, जब्त किए गए 837 नशीले सीरप को नेवई थाना क्षेत्र के नेवईभाठा में निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया। पुलिस के अनुसार,यह पूरी कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग और पुलिस मुख्यालय रायपुर के नारकोटिक्स सेल के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति के समन्वय से की गई। नष्टीकरण के दौरान डीआईजी/एसएसपी विजय अग्रवाल,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर शोभराज अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी और प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी अशोक अग्रवाल समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े सभी जरूरी नियमों का पालन किया गया। पुलिस के मुताबिक, नष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया में पर्यावरण विभाग और संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति ली गई थी। निर्धारित सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए जब्त सामग्री का सुरक्षित और विधिसम्मत निपटारा किया गया।

पुलिस की गिरफ्त में क्रिश्चियन फोरम अध्यक्ष अरुण पन्नालाल,एमएलए अजय चंद्राकर ने बताया धर्मांतरण के बड़े रैकेट का सरगना

रायपुर, 08 अगस्त 2026। भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी करने पर क्रिश्चन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी तो एक घटना मात्र हैं। दरअसल, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का अरुण पन्नालाल सरगना है, जिसकी पूरी हिस्ट्री जांचनी चाहिए। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि अरुण पन्नालाल खुद कब धर्मांतरित हुए? कितने संस्थाओं से उन्हें पैसे मिले? इसका उपयोग कहां हुआ? आजीविका कैसे चल रही है? ऐसे सारे विषय में प्रशासन को जांच करना चाहिए। विदेशी फंडिंग के यहां के सरगना हैं पन्नालाल। मैं मांग करता हूं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच की जाए। वहीं अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बजरंग दल और आरएसएस के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इसकी निंदा करती है। सरकार के लोगों को इस पर आत्म अवलोकन करना चाहिए। धर्म स्वातंर्त्य विधेयक को लेकर लोगों को उकसाकर कार्रवाई कर रहे हैं, हिंदुस्तान सभी लोगों का है,यहां संत महात्माओं का आदर है। ट्रेनिंग के बाद अब कांग्रेस जिलाध्यक्षों को पार्टी हाईकमान के रैंकिंग देने पर अजय चंद्राकर ने कहा कि राहुल गांधी के पास अभी समय नहीं हैं। वो सोशल मीडिया में पेट्रोलियम गाड़ी का ढक्कन खोलने,बंद करने में व्यस्त हैं, ऐसे में रैंकिंग के लिए समय कहां होगा। उन्होंने कहा कि रैंकिंग की बात फर्जी समाचार है,ऐसा मुझे लगता है। दरअसल,कांग्रेस के पास ना कार्यकम है, ना उद्देश्य है, और ना ही विजन है। किसी तरह से अपने चले आ रहे कैडर को व्यस्त रखना है। तो उठक-बैठक कराते रहते हैं, और कुछ नहीं है। अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा में दूध में मक्खी की तरह निकाले दिए गए हैं अजय चंद्राकर। वे उललू-जुलूल बात करते हैं। ई20 पेट्रोल का मुद्दा आमजनता की समस्या है। अजय चंद्राकर को ये खराब लग रहा है, क्योंकि उनके आंखों में चाटुकारिता की पट्टी बांधी है।

छत्तीसगढ़ में 24 आईएफएस अधिकारियों का ट्रांसफर गणवीर धम्मशील बने वन विभाग के विशेष सचिव

रायपुर,08 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शासन ने 24 आईएफएस अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं के आदेश जारी किए हैं।

अधिकारियों को अलग-अलग वनमंडलों और विभागीय संस्थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जारी आदेश के मुताबिक, गणवीर धम्मशील को वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। जबकि उत्तम कुमार गुप्ता को इंद्रावती टाइगर रिजर्व का प्रभारी

मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। दुलेश्वर प्रसाद साहू को मनेन्द्रगढ़ वनमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंकज राजपूत को रायपुर का नया वन उप संरक्षक बनाया गया है। प्रभाकर खलखो को सरगुजा कार्य आयोजना वनमंडल का प्रभारी वन संरक्षक बनाया गया है।

वन विकास निगम में 3 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति : संजय यादव, गीष्मी चांद और ऋषभ जैन को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में प्रतिनियुक्ति दी गई है। वहीं, पंकज कुमार कमल को वन विकास निगम से वापस लेते हुए बलौदाबाजार वन उप संरक्षक बनाया गया है।

लघु वनोपज संघ और PCCF कार्यालय में भी बदलाव : अभिषेक जोगावत को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ में उप महाप्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रौनक गोयल को PCCF कार्यालय में वन उप संरक्षक बनाया गया है।

मुक्तिधाम में पालतू कुत्ते के अंतिम संस्कार पर मचा बवाल, भड़के मोहल्लेवासी,थाने पहुंचा मामला

बिलासपुर,08 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुक्तिधाम में पालतू कुत्ते का दाह संस्कार करने को लेकर विवाद हो गया। स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताते हुए विरोध किया। पार्षद की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। घटना तोरवा थाना क्षेत्र की है। कुदुदंड क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के पालतू डॉग की मौत हो गई थी। परिवार का कहना है कि डॉग उनके लिए परिवार के सदस्य की तरह था। इसी भावनात्मक जुड़ाव के चलते वे उसे अंतिम विदाई देने के लिए तोरवा मुक्तिधाम ले गए। परिवार के मुताबिक, अनुमति लेकर हिंदू रीति-रिवाज से उसका दाह संस्कार किया गया। वहीं, स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। उनके मुताबिक मुक्तिधाम के केयरटेकर ने 2 हजार रुपए लेकर डॉग के दाह-संस्कार की अनुमति दी। इसके लिए नगर निगम से किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। उनका कहना है कि मुक्तिधाम में किसी पशु का दाह संस्कार करना धार्मिक परंपराओं और जनभावनाओं के खिलाफ है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बनी।

सेन समाज सनातन परंपराओं और सामाजिक समरसता का मजबूत आधार : सीएम साय

रायपुर,08 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सेन समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। इस समाज ने सदियों से भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था,संस्कारों और समरसता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत रत्न जननायक ।कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता का इस समाज से होना पूरे सेन समाज के लिए गौरव की बात है। सेन समाज केवल अपनी पारंपरिक सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक समाज के प्रत्येक संस्कार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समाज सनातन परंपराओं और संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित सेन शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेन समाज को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सेन समाज के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। उन्होंने कहा कि सेन समाज और अन्य पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उस समय अनेक महत्वपूर्ण पहल की गईं। सैलून संचालन के लिए सेन समाज के लोगों को किट, कुम्हारों को बैटरी चलित चाक और बढ़ई समाज के लोगों को कारपेंट्री किट देने की शुरुआत भी इसी दिशा में की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेन समाज की आज की आवश्यकताओं और मांगों पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर नया रायपुर में चौक का नामकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नामकरण के लिए कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने सेन समाज के विकास और कल्याण के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुनर और प्रतिभा का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर वंचित वर्गों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। आज उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी सेन समाज से विधायक रिकेश सेन और छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सु।मोना सेन समाज की सेवा और प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब केश शिल्प कल्याण बोर्ड को युवा नेतृत्व मिला है, निश्चित रूप गौरी शंकर श्रीवास के नेतृत्व में सेन समाज को आगे बढ़ाने का काम तेजी से होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पारंपरिक हुनर और छोटे-छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता, ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को भी सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रामीण और सामान्य परिवेश में रहकर उत्कृष्ट कार्य किया है। इससे देश में हुनर और श्रम के प्रति सम्मान की भावना मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई वर्षों में विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करने का काम तेजी से किया गया है।

हाईकोर्ट बोला...फुटपाथ पर पैदल चलना मौलिक अधिकार

बिलासपुर में फुटपाथ पर बनाया सड़क,अतिक्रमण भी,निगम कमिश्नर से पूछा...बचाने क्या किया

बिलासपुर,08 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क निर्माण के दौरान कई जगह फुटपाथ गायब हो गए हैं। वहीं, अवैध कब्जे और अनियंत्रित पार्किंग के कारण पैदल चलने वालों के लिए परेशानी और सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने निगम आयुक्त से पूछा है कि फुटपाथों को बचाने और अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में शपथपत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पैदल चलना संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ऐसे में नगर निगम

की जिम्मेदारी है कि वह फुटपाथों का संरक्षण करे और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त रखे। डिवीजन बेंच ने निगम आयुक्त से यह भी पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब तक जमीन पर क्या ठोस कार्रवाई की गई है।

आरटीआई और शिकायतों के बाद भी नहीं जागा प्रशासन : याचिकाकर्ता संस्कार राजपूत ने जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि फुटपाथों पर अवैध कब्जे और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के कारण बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों के लिए सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम और पुलिस प्रशासन से कई बार शिकायत करने के साथ ही आरटीआई के जरिए भी जानकारी मांगी गई, लेकिन इसके बावजूद समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

प्रशासन के दावों की खुली पोल : सुनवाई के दौरान नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि अतिक्रमण हटाने, मल्टीलेवल पार्किंग बनाने और सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि साल 2024 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 67 हजार से ज्यादा चालान काटे गए।

फोटोग्राफ से कोर्ट में बेनकाब हुए प्रशासन के दावे

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में हाल के फोटोग्राफ और मीडिया रिपोर्ट पेश कर प्रशासन के दावों पर सवाल उठाए। याचिका में कहा गया कि कागजों में कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति अब भी जस की तस है। फुटपाथों पर आज भी दुकानदारों का कब्जा है और वाहन खड़े किए जा रहे हैं। वहीं, शहर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर कोई ठोस और दीर्घकालिक नीति भी नहीं है। फिलहाल, मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

शिक्षा विभाग ने निकाला नया जुगाड़, अब स्कूलों के कर्मचारी संलग्न करने की बजाय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाएंगे कलेक्टर-कमिश्नर कार्यालय

रायपुर,08 अगस्त 2026। प्रदेश के प्रशासनिक दफ्तरों में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नया तरीका निकाला है। संलग्नीकरण खत्म होने के बाद अब स्कूलों में पदस्थ लिपिक और भृत्यों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।

हाल ही में प्रदेश स्तर पर शिक्षा विभाग में संलग्नीकरण समाप्त कर कर्मचारियों और शिक्षकों को वापस स्कूलों में भेजा गया था। इसके बाद कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालयों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने लगा। जिलों में प्रशासनिक कार्यों के लिए अस्थायी रूप से लगाए गए स्कूलों के गैर-शैक्षणिक स्टाफ के हटते ही दफ्तरों में कर्मचारियों की भारी कमी हो गई। इस समस्या को हल करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक अब आवश्यकता पड़ने पर स्कूलों में पदस्थ लिपिक और भृत्यों को प्रतिनियुक्ति पर कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालय भेजा जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया है कि 'उपरोक्त विषयांतर्गत संभागायुक्त व कई जिलों के कलेक्टरों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले के अंतर्गत शालाओं में पदस्थ गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की कार्यालयीन व्यवस्था के अंतर्गत संलग्नीकरण किया गया था।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)